सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 217, नई दिल्ली । बुधवार, 16 अक्टूबर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन में जिसने अपनी जीभ को संभालना सीख लिया, वो जीवन को भी संभाल लेगा, क्योंकि जीभ का स्वाद स्वास्थ्य खराब करता है और वाणी संबंध खराब कराती है।

03 वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर सीएम आतिशी ने दिए निर्देश

06 त्योहारी सेल भरोसे बैठा बाजार

08 स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्राथमिकता – के रवि कुमार

दिल्ली परिवहन विभाग प्रदुषण बढ़ते ही राजस्व इजाफा करने में हो जाता है व्यस्त

संजय बाटला

दिल्ली परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग जो दिल्ली में पंजीकृत वाहनों और वाहन मालिकों की ग़लती नहीं होने पर भी वाहन चालकों और मालिकों से सरकारी राजस्व में इजाफा करवाने के लिए प्लान बनाने और उस पर अपने पद के बल का प्रयोग कर जुर्माना वसूलने में व्यस्त है।

क्या सरकार का परिवहन विभाग को बनाने का यही उद्देश्य था या परिवहन विभाग जनहित में जनता के हित के मद्देनजर बनाया गया था ?

आज परिवहन विभाग में आला पदों (परिवहन आयुक्त और विशेष परिवहन आयुक्त)पर जो प्रशासनिक अधिकारी आसीन हैं उनके द्वारा जारी आदेश, दिशा निर्देश, एडवाइजरी खुले तौर पर यह सिद्ध कर रहे है की परिवहन विभाग को सरकार द्वारा खोलने का उद्देश्य मात्र जनता से किसी भी रुप में राजस्व में इजाफा करवाने के प्रति खोला गया है।

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से पूर्व में जिस भी पार्टी की सरकार रही उनके कार्यकाल में परिवहन विभाग द्वारा जनता के हित में बहुत से कार्य किए गए

1. जनहित में क्षेत्रीय कार्यालयों को खोला गया,
2. जनहित में सार्वजनिक सवारी सेवा वाहनों को खरीदकर चलवाया गया
3. जनहित में सार्वजनिक सवारी सेवा की पूर्ति करने के उद्देश्य से निजी वाहन मालिकों को भी परमिट जारी किए गए
4. दिल्ली में निजी एकल सार्वजनिक सवारी सेवा वाहनों को उपयोग करने वालों के लिए (आटो, टैक्सी, रेडियों टैक्सी एवम्-अन्य स्कीम के तहत) परमिट जारी किए गए
5. सार्वजनिक सवारी सेवा वाहनों के इजाफे के प्रति कई स्कीम लागू करी (फटफट सेवा, इको फ्रैंडली सेवा, आरटीवी सेवा, मेट्रो फीडर सेवा, ग्रामीण सेवा इत्यादि)
6. दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत डीज़ल वाहनों को बन्द कर सीएनजी वाहनों को व्यवसायिक श्रेणी के लिए शामिल किया
7. दिल्ली में हर सड़क और क्षेत्र में वृक्षों का रोपण करवाया
8. दिल्ली को जाम मुक्त करने के उद्देश्य से नई तकनीक से फ्लाई ओवर बनवाए
9. दिल्ली में मेट्रो रेल का संचालन शूरु करवाया

इतना सब करते रहते हुए कभी जनता को प्रदुषण जिसका मुख्य कारक खुद सरकारे है के लिए

1. ना तो जनता पर किसी प्रकार का जुर्माना लगवाया
2. ना कभी ओड इवन जैसे क़ानून लागू किए
3. ना जनता के घरों में खड़े वाहनों को उठवाकर किसी परिवहन विभाग के प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलर को सुपुर्द करवाया

4. ना कभी दिल्ली में दिवाली महोत्सव पर हिन्दुओं की खुशी को कम करने के लिए बम पटाखों पर रोक लगाई
5. ना कभी वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए

इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो

1. जनता
2. माननीय उच्चतम न्यायालय
3. माननीय एनजीटी
4. प्रदूषण नियंत्रण विभाग (भारत एवम्-दिल्ली)
5. माननीय गृह मंत्री भारत सरकार
6. माननीय परिवहन मंत्री भारत सरकार
7. माननीय उपराज्यपाल दिल्ली
8. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली
9. मुख्य सचिव दिल्ली
10. मुख्यमंत्री दिल्ली
11. मंत्री परिवहन दिल्ली
12. वायु गुणवता आयोग
13. आयुक्त परिवहन दिल्ली
14. आयुक्त एमसीडी दिल्ली

के लिए याद करने और रखने योग्य है की उस समय दिल्ली में पेट्रोलियम पदार्थ जिनका उपयोग होता था या दिल्ली में उपलब्ध था वह भारत स्टेज 2/3 , यूरो 2/3 मानक का था और आज 2021 से भारत देश खास तौर से दिल्ली में पेट्रोलियम पदार्थ भारत स्टेज 6, यूरो 6 मानक का ही बाजारों में उपलब्ध है।

यूरो 6 मानक का अर्ध दिल्ली में उपलब्ध पेट्रोलियम पदार्थ प्रदूषण मुक्त या दूसरे शब्दों में समझें तो बिना परेशानी उत्पन्न करने वाले पेट्रोलियम पदार्थ

वाहनों को चलने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक है और वाहनों के चलने से और पेट्रोलियम पदार्थ के जलने से ही प्रदूषण उत्पन्न होता है जब बाजार में इतना उच्च श्रेणी का पेट्रोलियम पदार्थ ही मात्र उपलब्ध है जैसा की भारत सरकार, राज्य सरकारे और जॉच प्रमाण जारी करने वाले एजेंसीज कहती और घोषणा कर रही हैं तो दिल्ली में पंजीकृत और दिल्ली में खरीदा गया पेट्रोलियम पदार्थ के प्रयोग के साथ कोई भी वाहन प्रदुषण कैसे बढ़ा सकता है ?

इसका ताजा ताजा एक उदाहरण भी उपलब्ध है कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में लगातार 10 दिन बारिश होती रही और आप सभी उन 10 दिनों की वायू गुणवत्ता की जाँच कर सकते है की एक भी दिन दिल्ली का वायु गुणवता अंक 150 भी पार कर सका

कुल मिलाकर सिर्फ़ राजस्व में इजाफा करवाने के उद्देश्य की पूरती करने के प्रति दिल्ली में वाहनों पर बंदिश, वाहनों की आयु में कटौती और खड़े वाहनों को उठवाने की प्रक्रियाएं है रही है जब की इन तमाम गतिविधियों के बाद भी पिछले कई सालों में प्रदूषण नियंत्रण में नहीं उल्टा और अधिक होता जा रहा है।

दिल्ली परिवहन विभाग तो ऐसे विभाग है जिस पर दिल्ली के हरे भरे पेड़ों को कटवाने के एवज मे लाखों रुपए का जुर्माना तक इसी साल में लगे हैं तो उससे क्यो उम्मीद की जा सकती हैं दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के प्रति

दिल्ली में आसीन परिवहन आयुक्त और विशेष परिवहन आयुक्त दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि में आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को परेशान कर रहे है और साथ ही साथ नए बाजार में बिकने के लिए आए वाहनों के पंजीकरण को रोकने में अपना भरपूर प्रयास कर रहे है।

ऐसे में आप क्या उम्मीद करते है परिवहन विभाग के आला प्रशासनिक अधिकारी के रहतेः- क्या वह दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में सहयोगी हैं यह प्रदूषण के नाम पर जनता और राजस्व इजाफे में।

एलजी ने दूर की दिल्ली मेट्रो के एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर के निर्माण की बाधाएं, 4 साल से लटका था मामला

दिल्ली मेट्रो के एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर के निर्माण में आ रही सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। एलजी वीके सक्सेना ने खानपुर गांव में 1688 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यह मामला 2020 से लंबित था। इस निर्णय से आरके आश्रम-मजलिस पार्क और इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर पर इंटरचेंज स्टेशन के निर्माण में सुविधा होगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। एलजी वीके सक्सेना द्वारा दक्षिण दिल्ली के खानपुर गांव में 1688 वर्ग मीटर की भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दिए जाने के साथ ही दिल्ली मेट्रो के फेज-5 के एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। यह मामला वर्ष 2020 से लंबित था।

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में, एलजी ने शिक्षा विभाग की 1600 वर्ग मीटर भूमि को एक वर्ष के लिए डीएमआरसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए डीएमआरसी (DMRC) किराए के रूप में 13,37,135 रुपये देगा।

दो कॉरिडोर के लिए होगा इंटरचेंज

इस निर्णय से दिल्ली मेट्रो के आरके आश्रम-मजलिस पार्क और इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर पर इंटरचेंज स्टेशन के निर्माण में सुविधा होगी।

मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए जमीन का होगा इस्तेमाल

खाली पड़ी इस भूमि का उपयोग ईदगाह रोड पर बनने वाले भूमिगत नबी करीम मेट्रो स्टेशन से जुड़ी निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा। यह भूमिगत स्टेशन उसी जमीन के टुकड़े के नीचे बनेगा, जिसको शिक्षा विभाग से लेकर डीएमआरसी को हस्तांतरित किया गया है। एक बार निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भूमि के इस टुकड़े को वापस शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा।

चार जुलाई से लटका था मामला

गौरतलब है कि खानपुर में जमीन अधिग्रहण का मामला करीब चार वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जबकि डीएमआरसी ने इसके लिए सात जुलाई 2020 को अनुरोध किया था। एक बार जमीन के अधिग्रहण के बाद अब एरोसिटी-तुगलकाबाद मेट्रो कॉरिडोर के महत्वपूर्ण सेक्शन को एक वर्ष की समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली को मिलेगा लाभ

इससे दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले कॉलोनियों से एयरपोर्ट और मेट्रो की दूसरी लाइनों से जुड़ी जगहों पर आना-जाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही इस कदम से मेहरौली-बदरपुर रोड पर लगने वाले भयंकर जाम की समस्या का भी समाधान हो जाएगा।

इसी तरह, ईदगाह रोड पर नबी करीम मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन विकसित होने के बाद मेट्रो के आरके आश्रम-मजिलस पार्क और इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों की निर्बाध यात्रा में भी मदद मिलेगी।

जनकपुरी से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो परिचालन को लेकर आया अपडेट

फेज चार में जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो कॉरिडोर तैयार हुए दो माह से अधिक समय हो चुका है। 40 दिन पहले मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) भी इस कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन शुरू करने की स्वीकृति दे चुका है। फिर भी अब तक इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब इस माह जल्दी ही जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

वाहन खरीदने वालों को हाथों-हाथ दें आरसी, नहीं तो रद होगा ट्रेड प्रमाणपत्र

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सरकार वाहन खरीदारों को तत्काल पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवहन मंत्री गहलोत ने आरसी में देरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है जिसमें ट्रेड प्रमाणपत्र रद्द करना भी शामिल है। सरकार फिजिकल आरसी की जगह डिजिटल आरसी जारी करने पर विचार कर रही है। बैठक में वाहन पंजीकरण में देरी मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स पर गैर-अनुपालन और एचएसआरपी में बैकलॉग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी वाहन खरीदते समय लोगों को तत्काल आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) नहीं मिल रही है। इसे लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा, FADA) और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम, SIAM) के साथ बैठक की।

बैठक में वाहन पंजीकरण में देरी, मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स पर गैर-अनुपालन और उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) में बैकलॉग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। गहलोत ने वाहनों की खरीद पर मिलने वाली आरसी में देरी पर ट्रेड प्रमाणपत्र रद करने समेत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इसके साथ ही गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार फिजिकल आरसी की जगह डिजिटल आरसी जारी करने पर विचार कर रही है।

समय पर प्रमाणपत्रों की हो डिलीवरी

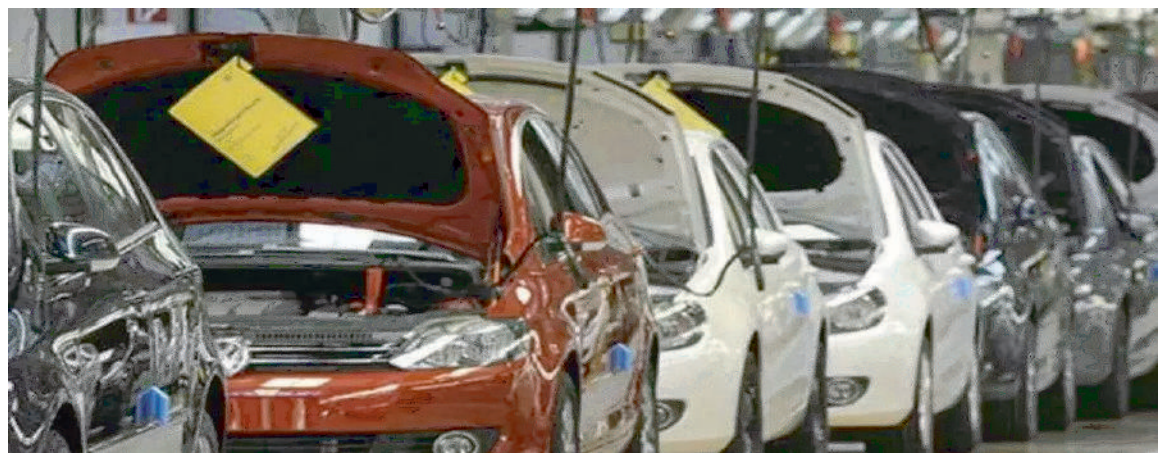

इसके लिए ही गहलोत ने परिवहन विभाग को व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि दिल्ली में वाहन मालिकों को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्रों (Vehicle Registration Certificate) की समय पर डिलीवरी और अनुपालन मानकों का पालन महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार इन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी गैर-अनुपालन से सख्ती से निपटा जाएगा।

पहले दिल्ली सरकार ने शुरू की थी ये सुविधा

बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2021 में डीलरों द्वारा आरसी छपाई और हाथों-हाथ आरसी प्रदान करने की सुविधा शुरू की थी। इसके तहत पहली आरसी 17 मार्च 2021 को जारी की गई थी। सितंबर 2021 तक दिल्ली के सभी स्व-पंजीकरण डीलरों को आरसी प्रिंट करने का अधिकार दिया गया था।

किस वर्ष कितनी आरसी छपीं

दिल्ली में 263 डीलर हैं, जो अपने डीलर प्वाइंट पर आरसी प्रिंट करने के लिए अधिकृत हैं। जून 2024 तक डीलरों द्वारा कुल 15,11,428 आरसी प्रिंट की गई थीं। इसमें से 2021 में 3,07,630 आरसी छपीं, जो 2022 में बढ़कर 4,72,311 हो गईं। 2023 में यह संख्या बढ़कर 4,96,828 हो गई। अकेले जनवरी से जून 2024 तक कुल 2,34,659 आरसी, वाहन मालिकों को हाथों-हांथ जारी की गईं।

गहलोत जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश

गहलोत ने पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाने में मौजूदा बैकलॉग पर सियाम के साथ चर्चा की। सियाम ने बताया कि लगभग 17 लाख बुकिंग में से 13.5 लाख पहले ही पूरी हो चुकी हैं और बाकी पुराने सभी बैकलॉग को 3-4 दिनों में ख़त्म कर दिए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने सियाम को एचएसआरपी लगाने में हो रही देरी को कम करने के लिए आवश्यक क़दम उठाने के निर्देश दिए।

बिना अनुमति के वाहन बेचने की चिंता

इसके अलावा फाडा ने वैध ट्रेड सर्टिफिकेट या परिवहन विभाग से आवश्यक अनुमति के बिना वाहन बेचने वाले मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स के बारे में चिंता जताई। इसे गंभीरता से लेते हुए गहलोत ने परिवहन विभाग को इन आउटलेट्स पर नियमों के अनुपालन की कड़ाई से जांच कर उल्लंघन करने वाले किसी भी आउटलेट को परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

क्यों हर साल 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे? जानें इसका दिलचस्प इतिहास

क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर साल लाखों लोग भूख से मर जाते हैं और करोड़ों लोग कुपोषण का शिकार होते हैं? जी हां यह एक गंभीर समस्या है जिसके बारे में हमें सभी को जागरूक होने की जरूरत है। यही वजह है कि हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं इसका रोचक इतिहास।

हाल ही में जारी हुई ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2024 की रिपोर्ट ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है, जो देश में गंभीर स्तर के भूख की समस्या को दर्शाता है। यह डेटा हमें विश्व खाद्य दिवस (World Food Day 2024) की अहमियत को और गहराई से समझने पर मजबूर करता है।

भारत जैसे देश के लिए विश्व खाद्य दिवस (October 16) और भी जरूरी हो जाता है जहां अभी भी लाखों लोग कुपोषण का शिकार हैं। GHI रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बच्चों में कुपोषण और बाल मृत्यु दर काफी ज्यादा है। इस स्थिति में, हमें अपने खाद्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कई जरूरी कदम उठाने होंगे। जी हां, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक ने चांद पर कदम रख लिया है, लेकिन दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए रोज का खाना जुटाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। हां, हमने प्रगति जरूर की है, लेकिन भुखमरी और कुपोषण जैसी समस्याएं अभी भी हमारे समाज को दागदार कर रही हैं।

क्यों मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे?

भोजन को जीवन का आधार कहा जाता है। इसके बावजूद लाखों लोग रोजाना भूखे पेट सोते हैं। यह एक ऐसा सच है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया को याद दिलाना है कि भोजन सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है।

वर्ल्ड फूड डे मनाने की शुरुआत कैसे हुई?

1945 में, जब दुनिया अभी भी युद्ध के घावों से उबर रही थी, तब एक नई उम्मीद जगी। रोम में, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की स्थापना हुई। इस संगठन का जन्म हुआ ताकि दुनिया में हर व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन हो सके। विश्व खाद्य दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के 20वें महासम्मेलन में हुई थी। एफएओ, दुनिया भर में भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। एफएओ ने 1981 से हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाने का निर्णय लिया।

हर साल, 16 अक्टूबर को हम एफएओ की इस पहल को याद करते हैं। विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन, हमें याद दिलाता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ जीवन और एक बेहतर भविष्य का आधार है।

वर्ल्ड फूड डे 2024 की थीम

साल 2024 की थीम है- 'Right to foods for a better life and a better future' यानी बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हर इंसान को पौष्टिक भोजन का अधिकार है। इसके लिए हमें ऐसी खाद्य प्रणाली विकसित करनी होगी जो न सिर्फ लोगों को भोजन उपलब्ध कराए बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि यह प्रणाली टिकाऊ हो। हमें भोजन की बर्बादी को कम करने और उन सभी तक पौष्टिक भोजन पहुंचाने के उपाय खोजने होंगे जो लोग भूख और कुपोषण से पीड़ित हैं।

करवाचौथ व्रत के अगले दिन नहीं होना पड़ेगा गैस और एसिडिटी से परेशान, 5 फूड्स रखेंगे आपका ख्याल

करवा चौथ का व्रत (Karva Chauth Vrat 2024) कई महिलाएं करती हैं लेकिन इसके अगले दिन अगर आपको भी अपच गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है तो यह आर्टिकल आपके काफी काम आने वाला है। दरअसल यहां हम आपको कुछ ऐसे फूड्स (Post Karva Chauth Vrat Diet) के बारे में बताएंगे जिन्हें व्रत के अगले दिन खाना बेहद फायदेमंद है।

करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, लेकिन इस दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। बता दें, निर्जला व्रत के कारण शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और पोषक तत्वों की कमी भी महसूस करता है। ऐसे में गैस, एसिडिटी और सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, व्रत के अगले दिन कुछ खास चीजों का सेवन (Post Karva Chauth Vrat Diet) करना बेहद फायदेमंद होगा। आइए जानते हैं ऐसे 5 सुपरफूड्स (Foods To Avoid Acidity After Fasting) के बारे में जो आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगे।

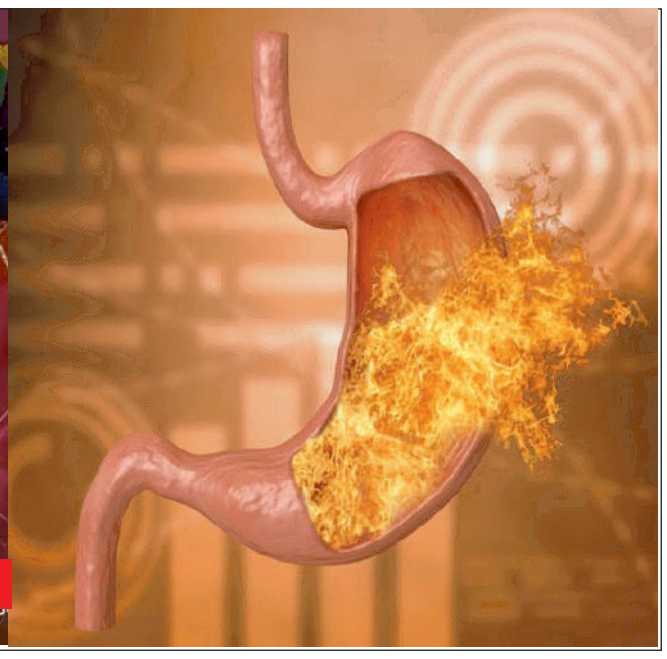

ड्राई फ्रूट्स

लंबे समय तक उपवास के बाद ड्राई फ्रूट्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इनमें मौजूद विटामिन और खनिज पदार्थ आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

हरी पत्तेदार सब्जियां

लंबे समय तक उपवास के बाद हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक और पत्ता गोभी आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर पाए जाते हैं जो आपको जरूरी पोषण देती हैं। ये सब्जियां न केवल आपको ऊर्जावान बनाती हैं बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखती हैं। आप इन्हें सलाद या सूप के रूप में खा सकती हैं।

नारियल पानी

व्रत के अलगे दिन सुबह-सवेरे कई महिलाएं चाय या कॉफी पीना पसंद करती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक दिन निर्जला व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह की शुरुआत इन चीजों के साथ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है? जी हां, अगर आप गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याओं से बचना चाहती हैं तो इसके बजाय नारियल पानी पी सकती हैं, जो आपको तुरंत एनर्जी भी देगा और इसमें मौजूद पोषक तत्व कमजोरी को भी दूर भगाएंगे।

दही

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स न केवल आपके पाचन को दुरुस्त रखते हैं बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। एक दिन के व्रत के बाद दही खाना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसे फलों और सब्जियों के साथ मिलाकर एक हेल्दी स्मूदी भी बना सकती हैं।

नींबू पानी

व्रत के अगले दिन नींबू पानी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट न केवल आपके शरीर को हाइड्रेट करते हैं बल्कि पाचन में भी सुधार करते हैं। अगर आपको व्रत के अगले दिन एसिडिटी या ब्लोटिंग की समस्या होती है, तो नींबू पानी आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है।

सेहत के लिए जहर से कम नहीं है टी बैग वाली चाय, नुकसान जानकर आप भी करने लगेंगे परहेज

*क्या आप भी वक्त और मेहनत बचाने के लिए **Tea bag** वाली चाय पीना पसंद करते हैं? अगर हां तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। मार्केट में इसके ढेरों फ्लेवर्स और वैरायटी मौजूद हैं जिन्हें लोग चुस्कियां लेकर पीते हैं। ऐसे में यहां हम आपको इस चाय से होने वाले कुछ ऐसे नुकसान (**Tea Bag Side Effects**) बताएंगे कि आप भी इसे पीना छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे।*

आजकल हम सभी एक बिजी लाइफस्टाइल का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में, चाय बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए टी बैग्स का इस्तेमाल खूब किया जाता है। आप ऑफिस में हों या फिर ट्रैवल कर रहे हों, टी बैग की मदद से मिनटों में चाय बनाई जा सकती है। बाजार में इसके कई फ्लेवर्स आसानी से मिल जाते हैं, जिन्हें लोग खूब स्वाद लेकर पाते हैं। ऐसे में, क्या आपने कभी सोचा है कि कम मेहनत और ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना बनने वाली टी बैग की यह चाय आपकी सेहत के लिए ठीक भी है या नहीं? आइए इस आर्टिकल में आपको इससे होने वाले नुकसानों (Bagged Tea Health Risks) के बारे में बताते हैं।

डायबिटीज के मरीज भूलकर भी न पिएं

सुबह की भागदौड़ या फिर ऑफिस वगैरह में कई लोग चाय बनाने के लिए टी बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई टी बैग्स में काफी ज्यादा कैफीन होता है? जी हां, यह कैफीन आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को बिगाड़ सकता है, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए। ऐसे में, अगर आप भी अक्सर ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव को लेकर परेशान रहते हैं तो टी बैग्स वाली चाय से दूरी बनाना ही बेहतर है।

एंटीऑक्सिडेंट्स की कमी

टी बैग्स में आमतौर पर पूरी चाय की पत्तियां नहीं होतीं।

इनमें चाय की पत्तियों को बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसे सीटीसी (CTC) या क्रश-टियर-कर्ल विधि कहते हैं। इस विधि में चाय की पत्तियों को बड़ी मशीनों में डालकर तब तक घुमाया जाता है जब तक कि वे छोटे-छोटे टुकड़ों में न टूट जाएं। इसके साथ ही, इन टुकड़ों में चाय की पत्तियों का पाउडर भी मिला होता है। बता दें, जब चाय की पत्तियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो उनमें मौजूद कई पोषक तत्व जैसे कि एल-थीनाइन और एंटीऑक्सिडेंट्स भी नष्ट हो जाते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को डिटॉक्स करने और ओवरऑल हेल्थ में सुधार करने में मदद करते हैं।

ब्लीच से होता है नुकसान

आप सोचते होंगे कि टी बैग्स में सिर्फ चाय की पत्तियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार टी बैग्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें ब्लीच का इस्तेमाल भी किया जाता है। यह ब्लीच चाय के साथ आपके शरीर में प्रवेश करता है और सेहत को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। इस ब्लीच से न सिर्फ चाय का स्वाद खराब होता है बल्कि इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व भी खत्म हो जाते हैं।

फंगस और कीड़ों का खतरा

कई बार टी बैग्स में फफूंद और छोटे-छोटे कीड़े भी पाए जाते हैं। ये हानिकारक जीव न सिर्फ चाय के स्वाद को खराब करते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। अगर आप यह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि आप जिस टी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं, तो बेहतर होगा कि आप किसी भरोसेमंद ब्रांड को चुनें और चाय बनाने से पहले टी बैग को अच्छी तरह से जांच लें।

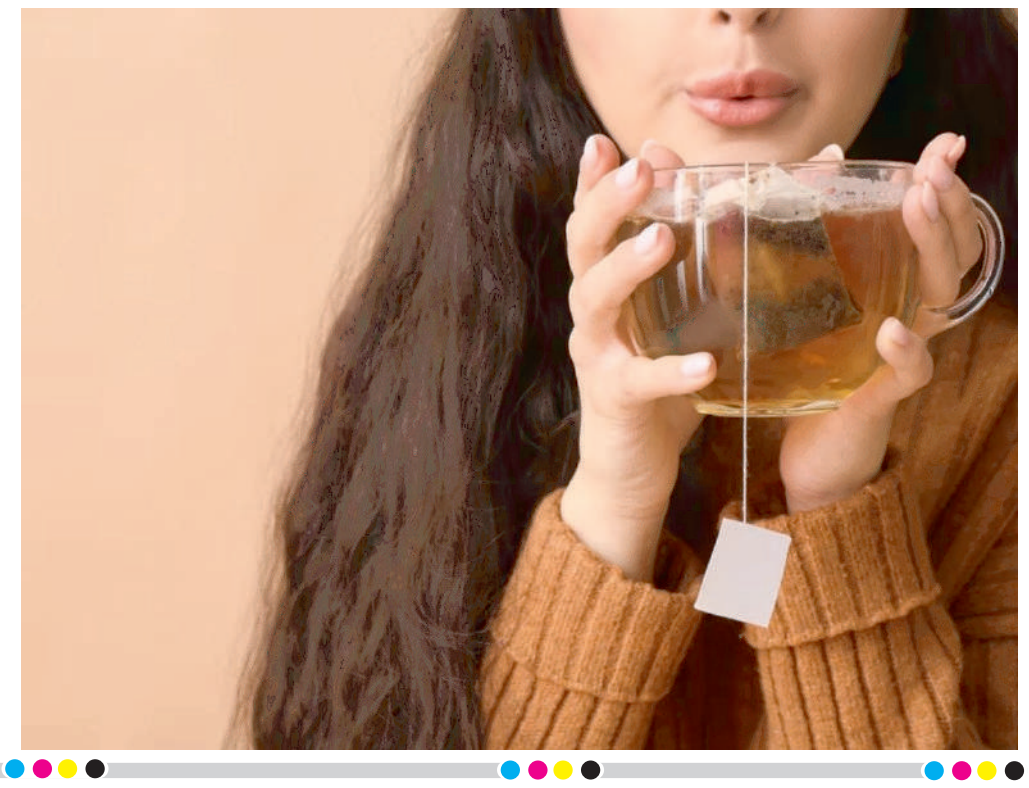

दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ बिगड़ी आबोहवा, इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। दिल्ली का एक्यूआई 200 से अधिक यानी 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है। मंगलवार को राजधानी में एक्यूआई 207 दर्ज किया गया। सोमवार को कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर 300 से भी ऊपर यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। इसे देखते हुए ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियां लागू की गई। इस बीच दिल्ली में तापमान गिरने लगा है।

नई दिल्ली। लगातार बदल रहे मौसम के बीच दिल्ली में अब सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। एसी और कूलर भी बंद होने लगे हैं। आसमान साफ रहने से न्यूनतम तापमान में भी कमी आ रही है। इसी क्रम में मंगलवार को दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी।

न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज

आज यानी मंगलवार को भी दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकल गया है। दिन चढ़ने के साथ साथ धूप भी तीखी होती जाएगी। हालांकि आंशिक रूप से बादल छाए रहने का भी अनुमान जताया गया है। आज का न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो इस सीजन का सबसे कम है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

अगले तीन-चार दिन तक साफ रहेगा आसमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी अगले तीन-चार दिन तक आसमान साफ ही रहेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी। धीरे-धीरे अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं, दिल्ली की हवा फिलहाल खराब ही चल रही है।

सुबह नौ बजे एक्यूआई 207 दर्ज

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक मंगलवार सुबह नौ बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 207 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर सीएम आतिशी ने उच्चस्तरीय बैठक कर दिए निर्देश

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर ''आप'' सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने ग्रैप-1 के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इस बाबत मंगलवार को सीएम आतिशी ने उच्च स्तरीय बैठक कर मौजूद हालात की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि जनवरी से 12 अक्टूबर तक 200 दिनों तक दिल्ली की हवा गुड कटेगरी में रही है, लेकिन पिछले दो दिनों से एक्यूआई पुअर कटेगरी में है। लिहाजा, सोमवार की शाम से ग्रैप-1 के नियम दिल्ली में लागू कर दिए गए हैं। धूल प्रदूषण रोकने के लिए 99 टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी, जबकि पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनसीआरटीसी और डीएमआरसी अपने निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाएंगी। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी समेत सभी विभाग सड़कों की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर पूरा करेंगे। सीएम ने दिल्ली की जनता से कार पूलिंग, पटाखे व कूड़ा न जलाने और प्रदूषण की सूचना ग्रीन दिल्ली एप पर देने की अपील की है।

दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि एक्यूआई बढ़ने के कारण सोमवार शाम से दिल्ली में ग्रैप-1 को लागू किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को मैंने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली सरकार के संबंधित सभी विभागों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा मीटिंग की। बैठक में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली मेट्रो, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, एनएचएआई, बिजली विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में ग्रैप-1 के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई।

सीएम आतिशी ने कहा कि ग्रैप-1 के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्माण साइटों पर धूल की रोकथाम है। इस बाबत डीपीसीसी की 33 टीमें, राजस्व विभाग की 33 टीमें और उद्योग विभाग की भी 33 टीमें बनाई गई है। यह सभी 99 टीमें रोजाना प्राइवेट और सरकारी निर्माण साइटों का स्थलीय निरीक्षण कर धूल प्रदूषण की रोकथाम के जारी नियमों के पालन का जायजा लेंगी। यह टीमें रोजाना अपने निरीक्षणों की रिपोर्ट ग्रीन वॉर रूम, पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेंगी।

सीएम ने कहा कि एमसीडी को कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट (सीएनडी वेस्ट) के निपटान को लेकर खास निर्देश दिए गए है। सीएनडी वेस्ट भी हवा की गुणवत्ता को ख़राब करता है। एमसीडी द्वारा सीएनडी वेस्ट को हटाने के लिए दिन में 79 टीमें और रात में 75 टीमें काम करेंगी। साथ ही ओपन बायोमास वेस्ट बर्निंग रोकने के लिए एमसीडी द्वारा दिन में 116 टीमें और रात में भी 116 टीमें तैनात की जाएंगी। ताकि किसी भी प्रकार की ओपन बर्निंग न की जाए।

सीएम आतिशी ने कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित कर वहाँ अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाए। क्योंकि त्यौहारों के सीजन में सड़कों पर आवाजाही ज्यादा होती है और ट्रैफिक देखने को मिलता है। इन सबके अलावा यदि ट्रैफिक पुलिस को दिल्ली सरकार के होम गार्ड की ज़रूरत है तो बुधवार तक दिल्ली पुलिस इस बाबत दिल्ली के गृह विभाग की सूचित करे और फिर गृह विभाग द्वारा ट्रैफ़िक जाम लगने वाले प्वाइंट्स पर होम गार्ड तैनात किए जाएँगे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में जनरेटर के इस्तेमाल पर रोकथाम लगाई जाएगी। खासतौर पर बैंक्वेट हॉल में यह देखा जाता है कि वहाँ बिजली के अस्थाई कनेक्शन की जगह डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रदूषण बढ़ने के इस समय में कहीं भी डीजल जनरेटर का इस्तेमाल न हो, इसलिए बिजली विभाग अपनी टीमें तैनात करेगी। साथ ही बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अगले तीन महीने तक, जब तक प्रदूषण ज्यादा होता है, बिजली कंपनियों से बात कर बिजली के अस्थाई कनेक्शन के चार्ज भी कम किया जाए।

सीएम आतिशी ने कहा कि, सरकार एक जागरूकता कार्यक्रम चलायेगी, जिसमें दिल्ली के लोगों को कार पूलिंग करने, दीपावली पर पटाखों का इस्तेमाल न करने की अपील की जाएगी। साथ ही सभी आरडब्ल्यूए से अपील की जाएगी कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स को इलेक्ट्रिक हीटर दे, ताकि लकड़ियां न जलाई जाए। दिल्ली सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि सिर्फ सरकार प्रदूषण नहीं रोक सकती है। जबतक दिल्ली के लोग साथ मिलकर आगे नहीं आएंगे, तबतक प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकेगा। इसलिए दिल्ली के लोग कार पूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, दीपावली में पटाखे न जलाएं, कहीं भी कूड़ा न जलाएं और कहीं भी प्रदूषण होता देखें तो ग्रीन दिल्ली एप पर सूचित करें।

इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले से ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है। सरकार ने दिल्ली में ग्रीन वॉर रूम का संचालन शुरू कर दिया है और ग्रीन दिल्ली एप भी लॉन्च किया है। दिल्ली में पराली की घटनाओं को कम करने के लिए बायो डी-कम्पोजर का छिड़काव किया जा रहा है। चूंकि यह पूर्वानुमान था कि हवा की गति कम होने, बारिश बंद होने और तापमान कम होने पर मौसम के विपरीत होने से प्रदूषण बढ़ने लगता है। इसलिए, एक्यूआई 200 के पार जाने के बाद ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया है। इसे और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मंगलवार को सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार औऱ दिल्ली के परिवहन मंत्रालय औऱ इसके दिल्ली परिवहन विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार का पुतला दहन करने से रोका

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्सएसोसिएशन ने दिल्ली के टैक्सी बसों पर लगातार होने वाले अत्याचार के खिलाफ आज 15 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय पर दिल्ली सरकार औऱ दिल्ली के परिवहन मंत्रालय औऱ इसके दिल्ली परिवहन विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार का पुतला दहन करने के लिए गए लेकिन पुलिस ने दिल्ली सचिवालय जाने की इज्जाजत नहीं दी और और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स को बाल भवन आईटीओ के पास ही रोक दिया गया, और जब एसोसिएशन के लोगो ने वहीं भर्ष्टाचार का पुतला फुकने की कोशिश करी तो पुलिस ने तुरंत ही पुतलो को जब्त कर लिया और भर्ष्टाचार का पुतला दहन नहीं होने दिया.

एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की जब बुराई के प्रतीक रावण के हजारों पुतले दहन हो सकते है तो भ्रष्टाचार का पुतला दहन क्यों नहीं हो सकता ? ये एक बड़ा सवाल है???

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने एक ज्ञापन भी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी सिंह जी को उनके ऑफिस में दिया.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की हम काफी सालो से दिल्ली सरकार, उसके परिवहन मंत्रालय औऱ दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से हो रहे पेनिक बटन घोटाला, स्पीड गवर्नर घोटाला औऱ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घोटाला होने की लगातार शिकायत कर रहें हैं. बल्कि इसके अलावा MCD टोल टैक्स (RFID टैग) घोटाला, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घोटाला. दिल्ली में पंजीकृत टैक्सी बसों से MCD टोल टैक्स वसूली का घोटाला. प्रदूषण की आड़ में गाड़ियों को स्क्रैप (कूड़ा) बनाने का घोटाला.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की हम काफी सालो से इस भर्ष्टाचार के खिलाफ आंदोलन भी कर रहें है. लेकिन दिल्ली सरकार औऱ उसके परिवहन विभाग हमारी मांगो को अनसुना कर रहा है बल्कि पेनिक बटन जो की पेहले इनका विभाग 2019 के बाद रजिस्ट्रेड हुई टैक्सी बसों मे लगाता था अब 2019 से पेहले रजिस्ट्रेड हुई टैक्सी बसों मे भी जबरजस्ती लगवाना शरू कर दिया. अभी दिल्ली में पेनिक बटन की वजह से काफी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेड नहीं हों रहीं है औऱ काफी गाड़ियों का परमिट औऱ फिटनेस नहीं हों रहीं है सबसे बड़ी बात ये है की इन पेनिक बटन के दबाने से कुछ नहीं होता. लेकिन दिल्ली के टैक्सी बसों के मालिकों को अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के समय पेनिक बटन (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) के 10 हजार से 15 हजार हर टैक्सी बसों के लिए देने पड़ते है. बल्कि अब ये हर 2 साल की फिटनेस के समय इन डिवाइस को चेक करने के नाम पर भी 5 हजार रुपये तक लेते है. औऱ इतना बड़ा भर्ष्टाचार निर्भया बलात्कार के नाम पर हों रहा है.

औऱ एक तरह से ये महिलाओ का भी मजाक बना रहें है क्योंकी ये महिलाओ की सुरक्षा के नाम भी भ्रष्टाचार कर रहें है.

आज तक दिल्ली सरकार या उसके परिवहन विभाग ने इसका कोई कॉल सेंटर नहीं बनाया, थोड़ा बहुत खाना पूर्ति के नाम पर ये गाडी की लोकेशन दिखाने की बाते ये करते है लेकिन पेनिक बटन दबाने से ना तो पुलिस आती ना ही ट्रांसपोर्ट विभाग का कोई कर्मचारी.

ऐसा ही स्पीड गवर्नर का मामला है इसमें भी करोडो रूपया का घपला हों चूका है.

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो की 200 रुपये की थी कुछ समय पेहले उसके 1000 रुपये से ज्यादा वसूल किये जा रहें है.

औऱ ये सब दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय औऱ दिल्ली परिवहन वीभाग की मिलीभगत से इनके द्वारा कुछ प्राइवेट वेंडर द्वारा किया जा रहा है. जिस से की दिल्ली सरकार औऱ इसका परिवहन मंत्रालय औऱ दिल्ली परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी अपने को बचा सके औऱ सारा आरोप प्राइवेट वेंडरस पर लगे.

इसी तरह दिल्ली का परिवहन विभाग प्रदूषण की आड़ में घर घर जाकर 10 से 15 साल की पेट्रोल /डीजल /सीएनजी की गाड़ियों को घर घर जाकर उठा रहा है औऱ अपने चहेते स्क्रैप डीलरों को गाड़ियाँ दिलवा रहा है.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आने वाले दिल्ली के चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे.

ऑटम शो, खास, विशिष्ट और प्रेरक संग्रह, सोर्सिंग का एक सुनहरा अवसर

सुषमा रानी

ग्रेटर नोएडा दिल्ली/एनसीआर । 58वां आईएचजीएफ दिल्ली मेला 16 से 20 अक्टूबर 2024 तक इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस संस्करण में 16 बड़े हॉल में 3000+ प्रदर्शकों की बारीकी से व्यवस्थित लेआउट का दावा किया जा रहा है, इनमें से 14, अहमडिस्प्ले सेगमेंट को समर्पित हैं, जिसमें हाउसवेयर, होम फर्नीशिंग, फर्नीचर, गिफ्ट एवं डेकोर, लैंप एवं लाइटिंग, क्रिसमस एवं फेस्टिव डेकोर, फैशन जूलरी एवं एक्सेसरीज, स्पा एवं वेलनेस प्रॉडक्ट, कारपेट एवं रग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, गार्डेन एक्सेसरीज, एजुकेशनल टॉयज और गेम्स, हस्तनिर्मित कागज उत्पाद और स्टेशनरी, तथा चमड़े के बैग शामिल हैं। यहां आने वालों आगंतुक, हॉल में प्रदर्शक बूथों के अलावा इंडिया एक्सपो सेंटर की विभिन्न मंजिलों पर स्थित प्रमुख निर्यातकों के 900 मार्ट/स्थायी शो रूम में भी जा सकेंगे।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के अध्यक्ष दिलीप बैद ने इस अवसर पर साझा किया, "दुनिया के सबसे बड़े सोर्सिंग आयोजनों में से एक, आईएचजीएफ दिल्ली मेला आयातकों, खरीदारों और खुदरा विक्रेताओं को भारत के बेहतरीन हस्तशिल्प को प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच, उद्यमियों, निर्यातकों और कारीगरों को जोड़ने की क्षमता के साथ मिलकर, भारतीय उत्पादों की विशिष्टता, गुणवत्ता, डिजाइन और मार्केटिंग क्षमता विदेशी खरीदारों में इनके प्रति विश्वास बढ़ाती है।

ईपीसीएच के महानिदेशक की भूमिका में चीफ मेंटर और आईईएमएल के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने कहा, "भारतीय उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग यह सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है कि भारतीय शिल्प कौशल दुनिया भर के घरों में अपनी जगह बना सके। होम डेकोर, लाइफस्टाइल, फैशन, फर्निशिंग और फर्नीचर के क्षेत्र में, आईएचजीएफ दिल्ली मेला एक गतिशील मंच के रूप में विकसित हुआ है, जो नए उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से परिचित कराता है, जबकि खरीदारों को उभरते आपूर्तिकर्ताओं से नए उत्पादों और विचारों की खोज करने की सुविधा देता है। कुशल कार्यबल और प्रचुर कच्चे माल द्वारा समर्थित भारत का हस्तशिल्प क्षेत्र निर्यातकों को इनोवेशन और कस्टमाइजेशन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ईपीसीएच द्वारा समर्पित और समर्थित डिजाइन, पूर्वानुमान और बाजार विश्लेषण प्रदर्शकों को बोल्ड और विशिष्ट उत्पादों को प्रदान करने का अवसर और शक्ति देते हैं, जिससे खरीदारों के लिए असीमित अवसर पैदा होते हैं।"

उन्होंने बताया, ₹आईएचजीएफ दिल्ली मेला - ऑटम 2024 में बिहार के पारंपरिक और समकालीन हस्तशिल्प की समृद्ध विविधता भी प्रदर्शित की जाएगी, जैसे सुजनी शिल्प, एप्लिक शिल्प, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की घास शिल्प और अन्य कारीगरी कार्य, जो राज्य के जीवंत कारीगर समुदाय की दक्षता को उजागर करेंगे। आगंतुकों को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करने वाले जटिल डिजाइनों को देखने और सराहने का अवसर मिलेगा।₹

आईएचजीएफ दिल्ली मेला-ऑटम 2024, स्वागत समिति के अध्यक्ष गिरीश कुमार अग्रवाल ने बताया, "प्रदर्शकों में जाने माने और पुरस्कृत शिल्पकारों ने एक थीम पर आधारित व्यवस्था की है, जो विरासत कौशल और क्षेत्रीय बारीकियों की समृद्धि को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे। राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे गए विशिष्ट कारीगर अपनी असाधारण शिल्प कौशल का प्रदर्शन करेंगे। उनकी भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि यह कार्यक्रम प्रमाणिक, क्षेत्र-विशेष की कारीगर कार्यों से संपन्न है, जो उन विभिन्न सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आगंतुक के पास यहां कुछ जीआई (भौगोलिक संकेतक प्रमाणित) उत्पादों समेत स्ट्रॉ पिक्चर मेकिंग, पेपर मैशे, कठपुतली मेकिंग, कुंदन मीनाकारी, सिल्वर फिलिग्री, लोक पेंटिंग इत्यादि जैसे शिल्पों में से चयन करने का मौका होगा, ₹वर्षों से यह मेला उद्यमियों, उत्पादकों, निर्यातकों और शिल्पकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय पहुंच के माध्यम से मार्केट लिंकेज बनाने का काम किया है और ऐसा करने में सक्षम होने की अपनी एक पहचान बनाई है। ईपीसीएच के वैश्विक प्रचार प्रयासों से हमें उम्मीद है कि खरीदारों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन विकास के नए रास्ते खोलेगा, व्यापार सहयोग और व्यापार विस्तार को बढ़ावा देगा।"

ईपीसीएच के उपाध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने बताया, "सबसे जीवंत और विविध व्यापार प्लेटफार्मों में से एक, आईएचजीएफ दिल्ली मेला खरीदारों को विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय हस्तशिल्प की व्यापक रेंज का पता लगाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। आईएचजीएफ दिल्ली मेला भारतीय निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन और संवर्धन बन चुका है, जो लगातार दुनिया भर से खरीदारों को आकर्षित कर रहा है। यह संस्करण उस विरासत को जारी रखने वाला है, जो वैश्विक खरीदारों को भारत के सभी क्षेत्रों के बेहतरीन हस्तशिल्प और उपहारों तक पहुंच प्रदान करता है। हमारे प्रदर्शकों ने मौजूदा बाजार ट्रेंड और खरीदारों की प्राथमिकताओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करते हुए उत्पाद डिजाइन और विकास में जबरदस्त प्रयास किया है। अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया और पहले से किए गए रजिस्ट्रेशन इस संस्करण के प्रति उनकी उम्मीद को दर्शाता है।"

ईपीसीएच के उपाध्यक्ष सागर मेहता ने कहा, "राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और ईपीसीएच के सहयोग से उत्पादों के एक डिस्प्ले में सस्टेनेबल डिजाइन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट किया जाएगा। यह पहल सामग्री (या माल) में नयापन, सामुदायिक सह-उत्पादन और चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांत पर फोकस करते हुए भारतीय हस्तशिल्प को आधुनिक सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों के साथ जोड़ती है। इसके अलावा, खरीदारों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मेले में रैंप शो, ट्रेंड को लेकर पूर्वानुमान, शिल्प का प्रदर्शन और नॉलेज सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिससे भारत की असाधारण शिल्पकला की गहरी समझ विकसित होगी।"

8 बिस्तरों वाली नई स्ट्रोक यूनिट का उद्घाटन किया

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग ने 8 बिस्तरों वाली अपनी नई स्ट्रोक यूनिट का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया है, जो इस क्षेत्र में तीव्र स्ट्रोक देखभाल में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वंदना तलवार ने उद्घाटन समारोह का नेतृत्व किया और रोगी देखभाल को बेहतर बनाने में यूनिट की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। डॉ. तलवार ने कहा, ₹यह स्ट्रोक यूनिट स्ट्रोक रोगियों को विश्व स्तरीय देखभाल प्रदान करने की हमारी अस्पताल की क्षमता में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करती है।₹ ₹यह स्वास्थ्य सेवा उन्नति और बेहतर रोगी परिणामों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण है। हमें अपने समुदाय में इस विशेष सुविधा को पेश करने पर बेहद गर्व है और स्ट्रोक उपचार और रिकवरी पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव की आशा है।₹ इस इकाई में 6 बिस्तरों वाली हाई डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) और न्यूरोलॉजी ICU में 2 नामित स्ट्रोक बेड शामिल हैं, जिसका आधिकारिक तौर पर एक समारोह में उद्घाटन किया गया, जिसमें अस्पताल के प्रशासक, चिकित्सा कर्मचारी और स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए।

डॉ. बी. के. बजाज, निदेशक प्रोफेसर और न्यूरोलॉजी के प्रमुख ने उद्घाटन की अध्यक्षता की, और स्ट्रोक से संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने में इकाई की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ₹यह समर्पित स्ट्रोक यूनिट उन्नत, गुणवत्तापूर्ण तीव्र स्ट्रोक देखभाल प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। एस्पिरेशन और संक्रमण जैसी जटिलताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, हमारा लक्ष्य हमारे स्ट्रोक रोगियों के लिए परिणामों में उल्लेखनीय सुधार करना है।"

नव स्थापित इकाई मल्टीपैरामीटर मॉनिटर से सुसज्जित है और इसमें न्यूरोलॉजिस्ट, समर्पित स्ट्रोक नर्सिंग अधिकारी और पुनर्वास कर्मियों सहित एक विशेष टीम है। यह बहु-विषयक दृष्टिकोण तीव्र स्ट्रोक रोगियों के लिए उनके आपातकालीन विभाग में प्रवेश करने के क्षण से लेकर उनकी रिकवरी प्रक्रिया तक व्यापक देखभाल सुनिश्चित करता है।

न्यूरोलॉजी के सीएमओ और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शिशिर चंदन ने मौजूदा सेवाओं में वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा, ₹जबकि हम तीव्र स्ट्रोक रोगियों के लिए थ्रोम्बोलिसिस प्रदान कर रहे हैं, यह नई सुविधा निस्संदेह हमारी देखभाल के मानक को बढ़ाएगी।₹ यूनिट की क्षमताओं को जोड़ते हुए, डॉ. चिराग, सहायक प्रोफेसर और न्यूरोइंटरवेंशनिस्ट ने समर्पित पोस्ट-प्रक्रिया देखभाल के महत्व पर ध्यान दियाः "हमारी मौजूदा थ्रोम्बेक्टोमी सेवाओं को अब विशेष पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल द्वारा पूरक किया जाएगा, जो इष्टतम रोगी रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है।" इस स्ट्रोक यूनिट के उद्घाटन से वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल भारत के उन कुछ केंद्रों में से एक बन गया है, जहां एक प्रतिबद्ध, व्यापक तीव्र स्ट्रोक देखभाल सुविधा है। जैसे ही यूनिट का संचालन शुरू होता है, यह देश में स्ट्रोक देखभाल के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से अन्य स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में इसी तरह की पहल को प्रेरित करता है। समारोह में अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, संकाय सदस्य, कर्मचारी और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए, जिनमें से सभी ने अस्पताल की सेवाओं में इस महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

गाजियाबाद में उपचुनाव की तारीख आई सामने, इस वजह से खाली हुई थी सीट

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ने वाला है। अब यूपी की रिक्त नौ सीटों पर उपचुनाव होगा है जिसके लिए चुनाव आयोग आज मंगलवार को एलान कर दिया है। इन नौ सीटों में गाजियाबाद की सदर सीट भी शामिल है। इस सीट पर भाजपा सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा के बीच कांटे की टक्कर होगी।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी पारा गरमाने वाला है। दरअसल, यूपी की नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (UP By Election 2024 13) नवंबर को होगा। इन नौ सीटों में गाजियाबाद की सीट भी शामिल है। (Result on 23 November) चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।

बता दें कि चुनाव आयोग ने आज ही उपचुनाव की तारीख का एलान किया है। गाजियाबाद की सीट पर भाजपा, सपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है।

लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने गाजियाबाद के सांसद रहे पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा था। अतुल गर्ग ने इस सीट पर जीत दर्ज करके पार्टी को मजबूत किया था।

कब होगी वोटिंग-

- 13 नवंबर को वोटिंग होगी।
- 23 नवंबर को मतगणना होगी।

यूपी की किन-किन सीटों पर होना है उपचुनाव-

1. कानपुर की सीसामऊ
2. प्रयागराज की फूलपुर
3. मैनपुरी की करहल
4. मिर्जापुर की मझवां
5. अंबेडकरनगर की कटेहरी
6. गाजियाबाद सदर (13 November Voting)
7. अलीगढ़ की खैर
8. मुरादाबाद की कुंदरकी
9. मुजफ्फरनगर की मीरापुर

बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा पर चुनाव का एलान नहीं किया गया है। हालांकि, यूपी की मिल्कीपुर सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। लेकिन अब इसी सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है।

कब खाली हुई गाजियाबाद की सीट

बताया गया कि गाजियाबाद की सदर सीट से 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के अतुल गर्ग विधायक बने थे। लेकिन पार्टी ने बाद में उन्हें लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और वह बड़े अंतर से जीत गए थे। वहीं, अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद गाजियाबाद विधानसभा सीट खाली हो गई थी। अब यहां उपचुनाव होना है।

विपक्ष में कांग्रेस को मिल सकता है टिकट

उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। वहीं गाजियाबाद की सीट के लिए कांग्रेस में दावेदारों की लंबी लाइन लगी है। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ कि यह सीट सपा के खाते में जाएगी या फिर कांग्रेस को मिलेगी।

आज जारी हुई चुनाव की अधिसूचना

विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। कांग्रेस में प्रत्याशी बनने के लिए एक लंबी कतार है। पार्टी द्वारा बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया को जिला प्रभारी के रूप में गाजियाबाद भेजा गया था, जिनके समक्ष 15 से अधिक ने विधानसभा उपचुनाव के लिए दावेदारी करते हुए बॉयोडाटा सौंपा।

सपा ने अधिकांश प्रकोष्ठ की कमेटियां की थी गठित

2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने रालोद के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। सपा की जिला और महानगर कमेटी गठित होने के साथ ही पार्टी के अधिकांश प्रकोष्ठ की कमेटियां बन चुकी हैं।

वहीं, उपचुनाव से पूर्व बूथ और सेक्टर अध्यक्षों की घोषणा के साथ ही उनकी निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। सपा संगठन मजबूती के लिए जहां कालेज और कॉलोनी व सोसायटी में सदस्यता अभियान चला रही है।

विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी प्रत्याशी और मिले मत

प्रत्याशी	पार्टी	मिले मत
अतुल गर्ग	भाजपा	150205
विशाल वर्मा	सपा-रालोद	44668
केके शुक्ला	बसपा	32691
शुशांत गोयल	कांग्रेस	11818

टिकट पाने की दौड़ में सबसे आगे कौन?

BJP-SP और BSP के दावेदारों के नाम आए सामने

उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2024 की तारीखों का एलान हो गया है। गाजियाबाद शहर सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भाजपा में संजीव शर्मा अजय शर्मा मयंक गोयल और अशोक मोगा दावेदार हैं। सपा-कांग्रेस गठबंधन में सुशांत गोयल डाली शर्मा आसिफ सैफी और तरुण रावत नाम चर्चा में हैं। बसपा परमानंद गर्ग को उतार सकती है।

गाजियाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। गाजियाबाद शहर सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा।

उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है, लेकिन इस विधानसभा सीट पर अब तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। दावेदारों को अब टिकट का इंतजार है, वहीं जनता को भी इस बात का इंतजार है कि राजनीतिक दल किस प्रत्याशी पर अपना दांव लगाते हैं।

टिकट को लेकर भाजपा में कांटे की टक्कर

शहर विधानसभा सीट पर लगातार दोबार से भाजपा अपनी जीत का परचम लहरा रही है। लगातार तीसरी बार भी जीत हासिल करने के लिए भाजपा नेता अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। टिकट के दावेदारों की बात करें तो भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, लोकसभा चुनाव में संयोजक रहे अजय शर्मा, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल और पंजाबी समाज से आने वाले अशोक मोगा का नाम है। अशोक मोगा भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और पूर्व में वह भाजपा में पश्चिम क्षेत्र के महामंत्री भी रह चुके हैं।

सपा-कांग्रेस गठबंधन दो दावेदार प्रबल

सपा-कांग्रेस के गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कांग्रेस में अगर टिकट के दावेदारों की बात करें तो सबसे मजबूत दावेदारी सुशांत गोयल की मानी जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशांत गोयल पूर्व सांसद सुरेन्द्र प्रकाश गोयल के बेटे हैं।

इनके अलावा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी रहीं डाली शर्मा के पिता नरेन्द्र भारद्धाज भी टिकट की दौड़ में है। यह पूर्व में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आसिफ सैफी और जिला महासचिव तरुण रावत का नाम भी टिकट के दावेदारों की लिस्ट में है।

बसपा चुनाव में उतार सकती है वैश्य प्रत्याशी को

बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर रवि गौतम को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही उनका टिकट काट दिया। अभी हाल ही में सपा में प्रदेश सचिव रहे परमानंद गर्ग ने बसपा की सदस्यता ली है। बसपा ने उन्हें शहर विधानसभा प्रभारी बनाया है।

सूत्रों का कहना है कि बसपा उन्हें इस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतार सकती है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी भी अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार सकती है।

सेटेलाइट ने पकड़ी जलती पराली, अधिकारियों में मचा हड़कंप; आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और चलवाया रोटावेटर

नोएडा में पराली जलाने का पहला मामला सामने आया है। दनकौर के बेला कलां गांव में किसानों ने करीब 15 बीघा खेत में आग लगाई थी। कृषि विभाग ने दोनों किसानों के साथ कंबाइन हार्वेस्टर मशीन संचालक के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पराली जलाने से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ जाता है।

ग्रेटर नोएडा। पंजाब के बाद अब एनसीआर में भी पराली में आग सुलगने लगी है। गौतमबुद्ध नगर में सोमवार को इस सीजन का पराली जलाने का पहला मामला सामने आया। जैसे ही सेटेलाइट से पराली जलाने की इमेज सामने आई, प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंच गई।

करीब 15 बीघा खेत में लगाई थी आग

रोटावेटर चलवाकर आग पर काबू पाया गया। दनकौर के बेला कलां गांव के किसान आमिर और शहजाद ने धान की कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई कराने के बाद करीब 15 बीघा खेत में आग लगाई थी।

कृषि विभाग ने दोनों किसानों के साथ कंबाइन हार्वेस्टर मशीन संचालक के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिसके बाद न केवल उनके खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी बल्कि विभाग प्राथमिकी भी दर्ज कराएगा।

पराली जलाने में अछूता नहीं जिला

खेतों में धान की कटाई का काम शुरू हो गया है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के साथ ही शहरों की हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। खेतों में किसान पराली न जलाएं शासन के आदेश पर न्याय पंचायत स्तर पर निगरानी टीमें गठित की गई है।

केंद्र सरकार सेटेलाइट से भी खेतों की निगरानी कर रही है। पराली जलाने के मामलों में जिला अछूता नहीं है। इससे पूर्व भी जिले में पराली जलाने की घटनाएं घट चुकी है। जिसके बाद विभागीय स्तर से न केवल किसानों पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई थी, बल्कि जिलाधिकारी के निर्देश पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी।

हर साल बढ़ जाता है प्रदूषण का स्तर

पराली जलने की वजह से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ जाता है। पिछले कई सालों से पराली जलने की वजह से प्रदूषण के हालात में कमोबेश कोई बदलाव नहीं आया है।

जमकर गरजा बुलडोजर, GDA ने कई स्थानों पर ध्वस्त किए अवैध निर्माण

गाजियाबाद में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामले में जीडीए की टीम ने सोमवार को कई स्थानों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। जीडीए की यह कार्रवाई हरनंदी नदी के डूब क्षेत्र और अन्य स्थानों पर की गई है। इसके अलावा नगर निगम ने इंदिरापुरम में ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त कराने के लिए चिन्हित किया है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की प्रवर्तन जोन चार की टीम ने सोमवार को हरनंदी नदी के डूब क्षेत्र और अन्य स्थानों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। जीडीए प्रवर्तन जोन चार की टीम ने डूब क्षेत्र में करीब 20 प्लॉट की अवैध बाउंड्री, बिल्डर का अवैध कार्यालय बुलडोजर चलाते हुए उसे ध्वस्त किया।

प्रवर्तन टीम ने न्यू पंचवटी कॉलोनी, शास्त्रीनगर, हरसांव, प्रताप विहार में भी कार्रवाई की। प्लॉट बाउंड्रीवाल के अलावा अन्य अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। न्यू पंचवटी के खसरा संख्या 67 पर भूखंड संख्या 303, 304 व 305 पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ा गया।

पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

हरसांव के खसरा संख्या 687 को ध्वस्त, प्रताप विहार सेक्टर 11 के भवन संख्या जी-28, महेंद्रा एन्क्लेव के डी-25 को सील कर दिया है। यह कार्रवाई प्रवर्तन दल सचल दस्ता के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।

दिवाली बाद इंदिरापुरम से हटेगा अवैध कब्जा

इसके अलावा नगर निगम ने दिवाली के बाद इंदिरापुरम में ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त कराने के लिए चिन्हित किया है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमणकारियों को हटाया जाएगा।

जीडीए में वार्ता के लिए पहुंचे किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने किया प्रदर्शन

उधर, वेव सिटी से प्रभावित किसान और प्राधिकरण सचिव के बीच बैठक होनी थी। निर्धारित समय पर किसान

जीडीए मुख्यालय पहुंच गए, लेकिन यहां आकर पता चला कि सचिव राजेश कुमार सिंह अवकाश पर हैं। इस पर किसानों ने रोष जताते हुए मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। बाद में अपर सचिव ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन देते हुए अगली बैठक 21 अक्टूबर को निर्धारित की।

भारतीय किसान संगठन के बैनर तले वेव सिटी के प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर किसानों का प्रतिनिधिमंडल जीडीए कार्यालय पहुंचा। यहां जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ बैठक होना निर्धारित था, लेकिन वह कार्यालय में नहीं मिले। इस पर किसानों को जानकारी दी गई कि वह अवकाश पर हैं। इस पर गुस्साए कुछ किसानों ने मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया।

सूचना पर अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर सभागार में वार्ता की। इस दौरान ओएसडी गूंजा सिंह भी मौजूद रहीं। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वासन दिया।

किसानों का कहना था कि कई बार उन्हें बुलाया जा चुका, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र यादव ने बताया कि लगातार वार्ता विफल हो रही है। इससे साफ है कि किसान हित को लेकर कोई गंभीर नहीं है। अपर सचिव ने अगली बैठक के लिए 21 अक्टूबर को किसानों को बुलाया है।

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार, सख्त कार्रवाई की दरकार

ललित गर्ग

बांग्लादेश की आबादी में 7.95 फीसदी-सवा करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो कुचक्र रचे गये, उसी तरह की साजिश बांग्लादेश में सिर उठा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो महीने में बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदू समुदाय पर हमले की 200 से ज्यादा घटनाएं हुई।

बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों एवं हिन्दुओं पर हो रहे हमलें, मशहूर जेशोश्वरी मंदिर में मुकुट का चोरी होना, हिन्दू अल्पसंख्यकों से जबरन इस्तीफा के लिये दबाव बनाने की घटनाएं, दुर्गा पूजा के पंडाल पर हमले चिन्ता के बड़े कारण हैं, यह हिन्दू अस्तित्व एवं अस्मिता को कुचलने की साजिश एवं षडयंत्र है, जिस पर भारत सरकार को गंभीर होने के साथ इन पर नियंत्रण की ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है। बीते अगस्त में शुरू हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बीच शेख हसीना का प्रधानमंत्री पद से हटना और भारत आने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों को असामाजिक तत्वों व कट्टरपंथियों द्वारा हवा दिया जाना शर्मनाक एवं विडम्बनापूर्ण है। नई दिल्ली में बांग्लादेश के हिन्दू-अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर बार-बार चिंता तो व्यक्त की जा रही है, लेकिन करारा एवं सख्त संदेश देने की कोई कोशिश होती हुई नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा सरकार के शासन में यदि ऐसी घटनाओं पर सख्ती नहीं बरती गयी तो फिर कब बरती जायेगी? यह विडंबना ही है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता व कार्यवाहक रूप में सरकार के मुखिया का दायित्व निभा रहे मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में हिन्दुओं एवं हिंदू पहचान के प्रतीकों को निशाना बनाया जाना बदस्तूर रहना किसी अन्तर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी पर्व पर आयोजित रैली को सम्बोधित करते हुए हिन्दुओं पर हो रहे इन हमलों को लेकर बड़ा संदेश दिया है, अपेक्षा है सरकार भी जैसे को तैसे वाली स्थिति में आकर हिन्दुओं की रक्षा की सार्थक एवं प्रभावी पहल करें।

बांग्लादेश की आबादी में 7.95 फीसदी-सवा करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो कुचक्र रचे गये, उसी तरह की साजिश बांग्लादेश में सिर उठा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो महीने में बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदू समुदाय पर हमले की 200 से ज्यादा घटनाएं हुई। आज बांग्लादेश सांप्रदायिकता एवं कट्टरता की आग में झुलस रहा है। सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोराहे पर खड़े बांग्लादेश में यह खतरा बढ़ता जा रहा है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए वहां अंतरिम सरकार ने हिंदू मंदिरों, गिरजाघरों या अल्पसंख्यकों के किसी भी धार्मिक संस्थान पर हमलों की जानकारी देने के लिए हॉटलाइन शुरू की थी, लेकिन कितनी ही शिकायतें मिलने के बावजूद उन पर कार्रवाई का न होना, इनको लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार का चुप्पी साधे रखना इस समस्या को गंभीर बना रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी वहां के हिंदुओं के लिए ही नहीं, भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं। इन हमलों एवं कट्टरतावादी शक्तियों का सक्रिय होना भारत एवं बांग्लादेश दोनों ही देशों के लिये खतरनाक है। कट्टरपंथियों के निरंकुश बने रहने से वहां की सरकार के इरादे और इच्छाशक्ति सवालों के घेरे में है।

भारत ने उचित तरीकों से ही इन घटनाओं को बेहद गंभीर बताते हुए इन पर न केवल चिंता जताई बल्कि अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। गौर करने की बात है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

का यह मसला धीरे-धीरे दोनों देशों के रिश्तों में खटास घोलते हुए एक अहम फैक्टर बनता जा रहा है। दुर्गापूजा के पंडाल में बम फेंके जाने की खबर स्वाभाविक ही बांग्लादेशी हिंदू बिरादरी को सहमा एवं डरा देने वाली है। जेशोश्वरी मंदिर में मां काली के ताज की चोरी इस मायने में भी अहम है कि यह ताज 2021 में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफे के तौर पर दिया था। यही नहीं, गुरुवार को चटगांव में दुर्गापूजा के दौरान कुछ लोगों द्वारा जबरन इस्लामी क्रांति के गीत गाए जाने की भी खबर आई। ऐसे में भारत अगर इन घटनाओं के पीछे सुनियोजित साजिश की आशंका जता रहा है तो उसे निराधार नहीं कहा जा सकता। ऐसे में लगातार बिगड़ती स्थितियों में यूनुस और उनके सहयोगियों को शासन और कूटनीति से जुड़े गंभीर मसलों पर परिपक्वता दिखानी होगी। आंदोलन से जुड़े गैर जिम्मेदार तत्व अनाप-शनाप आरोप लगाएं तो कुछ हद तक समझा जा सकता है लेकिन अगर शासन में बैठे लोग भी इन तत्वों का समर्थन करते हुए दिखें तो उसे सही नहीं कहा जा सकता। यह एक अराजकता की स्थिति है।

बांग्लादेश में बद से बदतर हो रहे हालात एवं हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, हमलों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सावधान कर कोई गलत नहीं किया। सक्रिय, व्यवस्थित और संगठित होकर ही ऐसी नापाक एवं संकीर्ण मानसिकताओं का माकुल जबाव दिया जा सकता है। भागवत ने कहा, ''दुर्बल रहना अपराध है, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए। अगर आप संगठित नहीं रहते हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।'' देश के दुश्मनों की ओर इशारा करते हुए मोहन भागवत ने कहा, ''भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब कोई भी देश जो आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी राह में अडंगा लगाने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए दूसरे देशों की सरकारों को कमजोर करना दुनिया में चलता रहता है।' लेकिन किसी राष्ट्र को कमजोर करने के लिये हिंदुओं यानी अल्पसंख्यकों पर हमलों का सहारा लेना, उन्हें प्रोत्साहित करना विकृत एवं अराष्ट्रीय मानसिकता का द्योतक है।

वैसे भी बांग्लादेश का विकास भारत के सहयोग पर निर्भर है, जिस भू-भाग को रवींद्रनाथ टैगोर 'आमार सोनार बांग्ला' (मेरा स्वर्णिम बंगाल) कहते थे, जहां की अर्थ-व्यवस्था एवं अन्य विकास योजनाएं भारत के सहयोग से ही आगे बढ़ती रही है, कभी भारत की कोशिशों से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। बांग्लादेश को आधी से ज्यादा बिजली भारत से मिलती है। अनाज की बड़ी सप्लाई भी भारत से होती है। अगर भारत ने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। बावजूद इन सब स्थितियों के वहां भारत-विरोधी घटनाओं का उग्र से उग्रतर होना खुद के पांव पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। बांग्लादेशी आकाओं को भगवान सद्बुद्धि दे। फिर भी अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो समय आ गया है कि हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं पर भारत कड़ा रुख अख्तियार करे। बांग्लादेश पर दबाव बनाने के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाना चाहिए। इसके लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने की जरूरत है।

हिन्दू धर्म भारत की संस्कृति एवं आत्मा है। हिन्दू धर्म संयम, त्याग और बलिदान का धर्म है। इसमें हमेशा दूसरे धर्मों को सम्मान देने का काम किया है। हिन्दू धर्म उदारता, प्रेम, आपसी सद्भाव और सहनशीलता पर आधारित धर्म है। हिन्दू धर्म की सहिष्णुता को कमजोर मानकर हिन्दू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य लगातार होता रहा है। वैसे तो प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं, किन्तु विकृत मानसिकता वाले लोगों ने हिन्दू धर्म को मध्यकाल से ही नीचा दिखाने की कोशिशें कीं। भारत पर लगातार आक्रांताओं के हमले होते रहे और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। हिन्दुओं के लाखों मंदिर तोड़े गए। हिन्दुओं से अपने ही देश में हिन्दू होने पर 'जजिया' यानि कर लगाया गया। पूर्व की सरकारों ने भी वोट की राजनीति के चलते हिन्दुओं को दोयम दर्जा पर रखा। फिर भी हिन्दू धर्म ने उदारता और सहनशीलता को नहीं छोड़ा। अगर हिन्दू कट्टर होता तो अन्य धर्मों के लोग भारत में नहीं दिखते। देश बंटवारे के समय पाकिस्तान में 20 प्रतिशत से ज्यादा हिन्दू थे लेकिन आज उनकी आबादी 2 प्रतिशत भी नहीं रही और भारत में मुसलमानों की आबादी 2 प्रतिशत से 20 प्रतिशत नहीं होती। यह हिन्दू उदारता का ही परिणाम है। लेकिन प्रश्न है कि आखिर कब तक हिन्दू ऐसी अग्नि परीक्षा देता रहेगा? कब तक हिन्दू की सहिष्णुता को कमजोरी मानकर उन पर अत्याचार होते रहेंगे? कब तक हिन्दू शक्तिसम्पन्न होकर भी निर्बल बना रहेगा? इन सवालों के जबाव तलाशने होंगे वर्ना हिन्दुओं को अस्तित्वहीन करने की कोशिशें कामयाब होती रहेगी।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

काइनेटिक इंजीनियरिंग अपनी सहायक कंपनी काइनेटिक वाट्स एंड वोल्ट्स में 30 करोड़ की करेगी निवेश

परिवहन विशेष न्यूज

काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड अनुसंधान, विकास और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनी सहायक कंपनी काइनेटिक वाट्स एंड वोल्ट्स में 30 करोड़ रुपये का निवेश करने की तैयारी में है।

पुणे स्थित ऑटो कंपोनेंट निर्माता ने पहले 2022 में काइनेटिक वाट्स एंड वोल्ट्स की स्थापना की घोषणा की थी, जो मोटर्स, एक्सल, फ्रेम, कंट्रोलर और बैटरी जैसे इलेक्ट्रिक वाहन घटकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह नया निवेश पहले की 18.5 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता पर आधारित है, जिससे सहायक कंपनी में कुल निवेश 48.5 करोड़ रुपये हो गया है।

काइनेटिक इंजीनियरिंग के प्रबंध निदेशक अजिंक्य फिरोदिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह नवीनतम पूंजी निवेश न केवल नवाचार के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, बल्कि अधिक टिकाऊ भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

इसलिए, इस निवेश का उद्देश्य भारतीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल, विश्वसनीय और उन्नत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधानों के निर्माण को सुविधाजनक बनाना है।

बेंगलुरु स्थित गैर-लाभकारी संस्था ने घरेलू हिंसा से

परिवहन विशेष न्यूज

डिजिटल व्यवसाय और आईटी सेवा कंपनी एनटीटी डेटा की वित्तीय सहायता से बेंगलुरु स्थित गैर-लाभकारी संस्था यूनाइटेड वे बेंगलुरु (यूडब्ल्यूबीई) ने ड्राइविंग प्रशिक्षण पूरा कर चुकी महिलाओं को पांच ई-रिक्शा वितरित किए हैं।

इस पहल को बेंगलुरु पुलिस और परिहार नामक एक गैर सरकारी संगठन ने समर्थन दिया है, जो कमज़ोर महिलाओं की मदद करता है। इसका घोषित लक्ष्य कमज़ोर समुदायों की महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है। प्रत्येक ई-रिक्शा में कैब एग्रीगेटर ऐप के ज़रिए सवारी के अनुरोधों को प्रबंधित करने के लिए एक स्मार्टफ़ोन दिया गया है।

एनटीटी डेटा के उपाध्यक्ष और विपणन प्रमुख अंकुर दासगुप्ता ने कहा, ₹हम उन पहलों का समर्थन करने में विश्वास करते हैं जो स्थायी और सार्थक बदलाव लाते हैं। ई-रिक्शा परियोजना एक अधिक समावेशी और समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है, जहां महिलाएं अपने भविष्य को नियंत्रित करने के लिए सुसज्जित हैं।"

बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने मीडिया को बताया, ₹परिहार ने घरेलू हिंसा की शिकार इन पांच महिलाओं के पुनर्वास में हमारी मदद की है। उन्हें ऑटो चलाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है और आरटीओ ने उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया है।"

यूडब्ल्यूबीई के सीईओ राजेश कृष्णन ने कहाः ₹हमारा मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, अधिक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

सात्विक ग्रीन एनर्जी को महाजेनको से 302 करोड़ रुपये का मिला ऑर्डर

परिवहन विशेष न्यूज

सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) से महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर 200 मेगावाट के अत्याधुनिक एन-टॉपकॉन 580Wp मॉड्यूल स्थापित करने का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 302 करोड़ रुपये है। इससे महाराष्ट्र में अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में बहुत सुधार होने की उम्मीद है, जिससे राज्य में हरित ऊर्जा समाधानों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकेगी।

यह ऑर्डर अक्षय ऊर्जा बाजार में कुशल सौर समाधानों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में सात्विक को विकास पथ पर स्थापित करता है। महाजेनको भारत की सुस्थापित बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है। सात्विक के प्रस्ताव में सात्विक एन-टॉपकॉन 580Wp शामिल है जो व्यवसाय में सबसे बेहतर और लोकप्रिय वस्तुओं में से एक है, और इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए काम करता है। ये मॉड्यूल अपने बेहतरीन प्रदर्शन और आउटपुट पावर के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं।

सात्विक ग्रीन एनर्जी के सीईओ प्रशांत माथुर के अनुसार, उनके एन-टॉपकॉन मॉड्यूल सख्त उद्योग मानकों के अनुसार बनाए गए हैं, जो दीर्घकालिक टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन की गारंटी देते हैं।

वर्तमान संदर्भ में, सात्विक ग्रीन एनर्जी अपने अक्षय ऊर्जा उद्योग में कई रणनीतिक बुनियादी ढांचे की उन्नति के लिए अधिक सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। फर्म उच्च-स्तरीय सौर पीवी मॉड्यूल विकसित कर रही है, जिसमें ₹0 बज़ बार₹, ₹24 बज़ बार₹ और उच्च दक्षता वाले हाफ कट मॉड्यूल जैसी विशेषताएं हैं। मॉड्यूल के अलावा अन्य ऊर्जा घनत्वों को बढ़ाने के लिए, यह इलेक्ट्रोलाइज़र बैटरी और स्टोरेज सिस्टम के निर्माण पर निवेश करने पर विचार कर रही है।

जितेंद्र ईवी यूनिक का टीजर जारी, जल्द होगा लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

नासिक स्थित ईवी निर्माता जितेंद्र ईवी ने नवंबर में 'यूनिक' नाम से एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। यह आगामी मॉडल कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मौजूदा लाइनअप, जेएमटी रेंज और प्राइमो रेंज में शामिल हो जाएगा।

हालांकि नए स्कूटर के बारे में पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जितेंद्र ईवी का दावा है कि यूनिक एक हाई-स्पीड स्कूटर होगा, इसलिए हम इसकी अधिकतम गति कम से कम 50 किमी प्रति घंटे -70 किमी प्रति घंटे होने की उम्मीद नहीं कर सकते।

इसके डिज़ाइन की बात करें तो, इस अपकमिंग स्कूटर में गोल LED हेडलाइट होगी और फ्रंट एप्रन पर जितेंद्र ईवी का लोगो होगा। हालाँकि, जितेंद्र ईवी ने खुलासा किया है कि स्कूटर में मर्दाना डिज़ाइन के साथ-साथ कई रंग भी होंगे।

जितेंद्र ईवी ने अभी तक स्कूटर के स्पेसिफिकेशन, कीमत या उपलब्धता के बारे में जानकारी जारी नहीं की है। नवंबर में लॉन्च की तारीख के करीब और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

सब्सिडी कोटा खत्म होने से मुंबई के लोगों ने खरीदी दशहरे में सिर्फ 2% ईवी

परिवहन विशेष न्यूज

प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार आम लोगों को ईवी खरीदने को प्रोत्साहित करने का सिर्फ दिखावा कर रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस बार मुंबई में दशहरे के दिन सिर्फ 2 फीसदी ईवी बिके। इसका प्रमुख कारण है कि इन वाहनों की बिक्री के लिए राज्य को जो सब्सिडी दी गई थी, उसका कोटा खत्म हो गया है।

मुंबई जैसे शहर में त्योहारों के दौरान वाहनों की खरीदारी सबसे अधिक होती है। इस दशहरे में मुंबई के उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत वाहनों में से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या सबसे कम है। पंजीकृत निजी दोपहिया और चारपहिया वाहनों में केवल 2.6 प्रतिशत ही इलेक्ट्रिक वाहन हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में कमी और चार्जिंग के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी में उदासीनता दिखा रहे हैं। मुंबई में बीकेसी, विक्रोली, सीएसएमटी, परेल, घाटकोपर, कुलाबा, गोरेगांव, कांदिवली (पूर्व) जैसी कुछ ही जगहों पर चार्जिंग स्टेशन हैं। एक चारपहिया वाहन को चार्ज करने में तीन से साढ़े तीन घंटे लगते हैं। इसलिए जब तक पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। सरकार ने 2025 तक 01 लाख दोपहिया और 10 हजार चारपहिया वाहनों पर सब्सिडी देने का कोटा मंजूर किया था। यह कोटा समाप्त हो चुका है और जब इस कोटे को बढ़ाया जाएगा तभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी फिर से शुरू की जाएगी, ऐसा परिवहन अधिकारियों ने बताया।

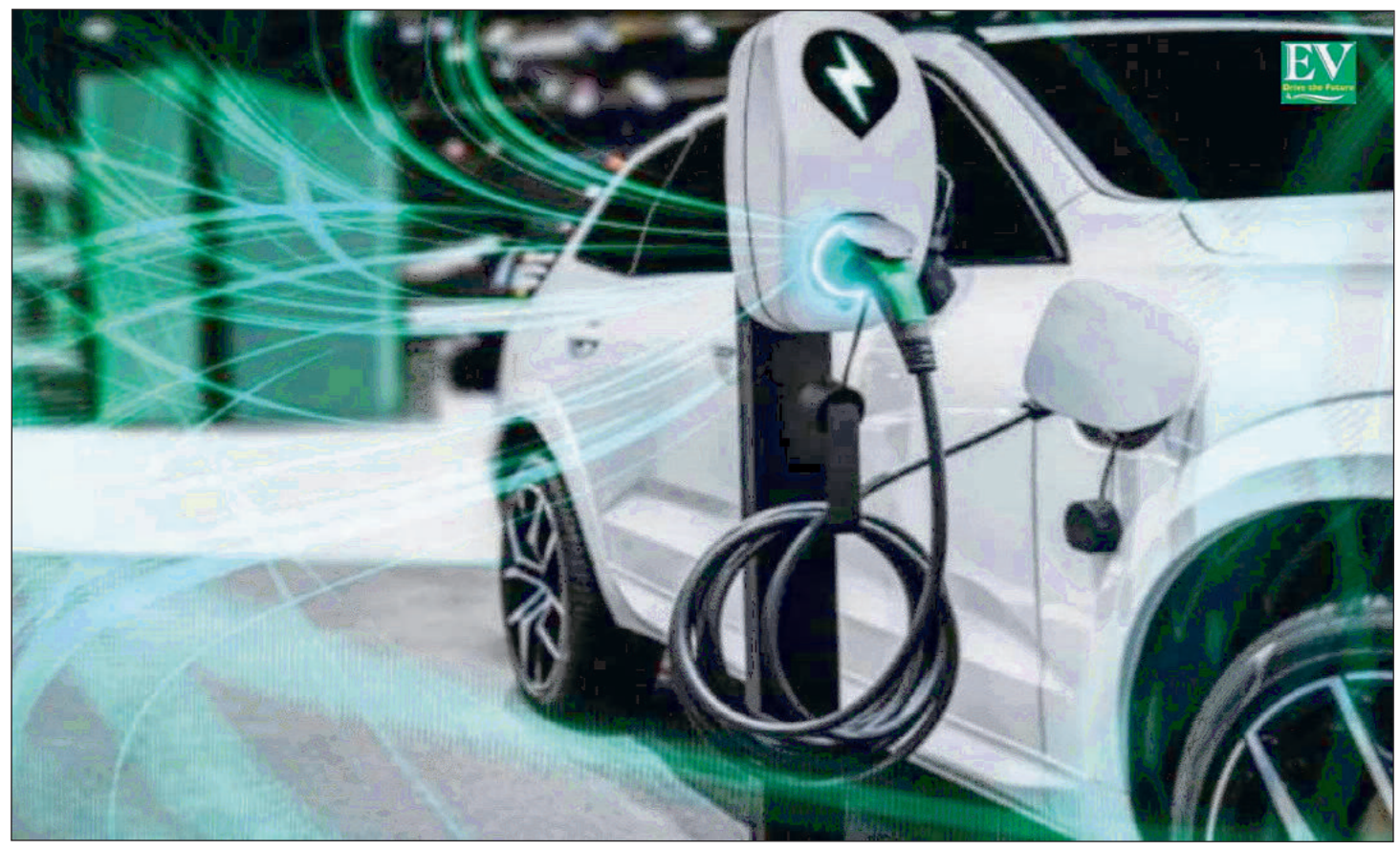

अधिकारियों के अनुसार 25 किमी प्रति घंटे से कम गति से चलने वाले दोपहिया वाहनों का पंजीकरण न होने के कारण यह संख्या कम हो सकती है। इसके अलावा वर्तमान में इलेक्ट्रिक के साथ-साथ हाइब्रिड वाहनों की मांग में वृद्धि भी इसका एक कारण हो सकती है।

इंटर्नशिप योजना के लिए 24 घंटे में 1.55 लाख युवाओं ने कराया पंजीकरण

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की 12 अक्टूबर को शुरुआत हो चुकी है। इसके शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही 1,55,109 उम्मीदवारों ने पंजीकरण करा लिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसरों का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस इंटर्नशिप योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट में पेश की थी।

इस योजना का उद्देश्य युवाओं की बेरोजगारी को दूर करना है, उन्हें प्रतिभा की तलाश कर रही शीर्ष कंपनियों से जोड़ना है। सरकार पायलट प्रोजेक्ट पर 800 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है, जिसमें दिसंबर के पहले सप्ताह तक इंटर्न के पहले बैच को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल 12 अक्टूबर को लाइव हो गया और पात्र उम्मीदवार नवंबर में चयन प्रक्रिया शुरू होने तक आवेदन कर सकते हैं।

सीएनबीसी-टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार चयनित उम्मीदवारों के पहले समूह को 8 से 15 नवंबर के बीच मध्य नवंबर तक इंटर्नशिप ऑफर मिल सकता है। ये इंटर्नशिप तेल, गैस और ऊर्जा, यात्रा और आतिथ्य, ऑटोमोटिव और बैंकिंग जैसे 24 क्षेत्रों में पेश की जाएगी, जो 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में अवसर प्रदान करेगी।

जुबिलेंट फूडवर्क्स, मारुति सुजुकी, लार्सन एंड टूब्रो, मुथूट फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी शीर्ष कंपनियों ने पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर इंटर्नशिप पोस्ट कर दी है। उपलब्ध भूमिकाएँ परिचालन प्रबंधन और उत्पादन से लेकर बिक्री और रखरखाव तक हैं, जो संभावित रूप से भारत के उभरते उद्योगों में कौशल को संबोधित करती हैं। यह योजना 21-24 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों के लिए खुली है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल डिप्लोमा से लेकर स्नातक डिग्री (बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए और बी.फार्मा) तक है।

आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से स्नातक या मास्टर डिग्री या उच्च डिग्री रखने वाले पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी कौशल या प्रशिक्षुता कार्यक्रमों में नामांकित लोग आवेदन नहीं कर सकते। निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, आवेदकों को प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम कमाने वाले परिवारों से आना चाहिए और जिनके परिवार में स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं वे पात्र नहीं हैं।

त्योहारी सेल भरोसे बैठा बाजार

विजय गर्ग

उपभोक्ता बाजार में माहौल का सुधरना कई कारणों से जरूरी भी है, क्योंकि इससे पहले चिंता और तनाव वाले कई संकेत आ चुके हैं या सामने खड़े हैं। सितंबर में जीएसटी वसूली का आंकड़ा सिर्फ 6 .5 प्रतिशत बढ़कर आया, जबकि इससे पहले यह 10 फीसदी से ऊपर की रफ्तार दिखा रहा था। औद्योगिक उत्पादन में भी कमजोरी दिखने लगी और पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आठ महीनों में सबसे नीचे पहुंच गया। यह इंडेक्स बड़ी कंपनियों में खरीदारी करने वाले मैनेजरों के बीच सर्वे करके बनता है।

गरबा डांडिया, नवरात्रि, रामलीला, दशहरा, दीपावली - देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग अंदाज में यह जश्न का मौसम होता है। इतना ही नहीं, यह तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि फिर दीपावली से बढ़ते हुए क्रिसमस और नए साल तक का पूरा वक्त त्योहारी मौसम या फेस्टिव सीजन कहलाता है। परंपरा है कि भारत के ज्यादातर त्योहार किसी न किसी तरह फसल से जुड़े होते हैं, यानी यह जश्न सिर्फ शहरों का नहीं, गांवों का या पूरे भारत का भी होता है।

बात सिर्फ घर-परिवार तक सीमित नहीं है। जब आप त्योहार के मूड में आते हैं, तो तैयारी भी करते हैं और खरीदारी भी । इसीलिए आपके आसपास के दुकानदारों से लेकर देश और दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों तक को इसी मौसम का इंतजार रहता है। मौजूदा साल खास है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से तेज आर्थिक तरक्की के बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि भारत के बाजारों में मांग कब लौटेगी। एक चावल से पूरे पतीले का हिसाब लगाने वालों को तो नमूना हाथ लग भी गया है। सितंबर के अंत में अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों और दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने बड़ी- बड़ी सेल लगाई। बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की शुरुआत तो 27 सितंबर से हुई, लेकिन प्राइम और प्लस जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम के मेंबरों के लिए यह एक दिन पहले खुल गई थी। आंकड़े आए हैं कि एक हफ्ते में ऑनलाइन रिटेल कंपनियों ने 55 हजार करोड़ रुपये या करीब साढ़े छह अरब डॉलर का सामान बेच डाला। यह पिछले साल की इसी सेल से 26 फीसदी ज्यादा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस साल जानकारों ने त्योहारी सीजन में कुल जितनी बिक्री का अनुमान लगाया था, उसकी आधे से ज्यादा बिक्री दशहरे के पहले ही हो चुकी थी। बिक्री के गणित को जोड़ने वाली मार्केट रिसर्च एजेंसियों का अनुमान था कि इस त्योहारी सीजन में करीब 12 अरब डॉलर की बिक्री होगी, जो पिछले साल से लगभग 30 फीसदी ज्यादा है। मगर पहले ही हफ्ते में बिक्री की रफ्तार उम्मीद से पार निकल गई। ऑनलाइन बिक्री का ज्यादातर हिस्सा मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन पर खर्च हुआ है। हालांकि, इसी हफ्ते के भीतर की खबर यह भी है कि तेजी के शुरुआती झोंक के बाद हफ्ता खत्म होते-होते बिक्री ठंडी पड़ने लगी। मार्केट रिसर्च करने वाले और इस कारोबार में लगे लोग भी मानते हैं कि ये सेल इसी तरह चलती हैं। शुरू में महंगी चीजें धड़ाधड़ बिकती हैं और उसके बाद लोग सस्ते माल की तलाश में लग जाते हैं। इसके बावजूद जिस रफ्तार से सेल चली, उससे उत्साह की लहर है।

उपभोक्ता बाजार में माहौल का सुधरना कई कारणों से जरूरी भी है, क्योंकि इससे पहले चिंता और तनाव वाले कई संकेत आ चुके हैं या सामने खड़े हैं। सितंबर में जीएसटी वसूली का आंकड़ा सिर्फ 6.5 प्रतिशत बढ़कर आया, जबकि इससे पहले यह 10 फीसदी से ऊपर की रफ्तार दिखा रहा था। औद्योगिक उत्पादन में भी कमजोरी दिखने लगी और पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आठ महीनों में सबसे नीचे पहुंच गया। यह इंडेक्स बड़ी कंपनियों में खरीदारी करने वाले मैनेजरों के बीच सर्वे करके बनता है। इनका मूड बिगड़ने का अर्थ है कि कंपनियां खरीदारी कम कर रही हैं। ऐसा तभी होगा, जब उनका माल आगे बाजार में बिक नहीं रहा हो या उनके पास नए ऑर्डर न आ रहे हों। इसी तरह कारों के बाजार में लगातार तीन महीनों से बिक्री गिरने की खबर आ रही है। वह भी तब, जबकि हर रोज अखबारों में कारों पर छूट और तोहफों के तरह-तरह के ऑफर दिख रहे हों। हालात चिंताजनक हैं, इसीलिए अब अर्थशास्त्रियों की उम्मीद दो चीजों पर टिकी हैं अच्छे मानसून का असर, यानी अच्छी फसल और आम आदमी की जेब, यानी बाजार में खरीदारी तेज होने की उम्मीद। खरीफ की बुआई के आंकड़ों से पहली उम्मीद तो पूरी होती दिख रही है। 27 सितंबर तक 11 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में फसल बोने की रिपोर्ट थी। यह सामान्य से बेहतर बुआई है। हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में असामान्य बारिश से फसल के खराब होने की खबरें भी आ रही हैं और सिर्फ बुआई हो जाना ही अच्छी फसल की गारंटी नहीं होता। मगर यहां किस्सा खेती से ज्यादा खरीदारी का है। अच्छी फसल का मतलब यह भी होता है कि गांवों में या उनके आसपास के बाजारों में बिक्री बढ़ेगी या लोग खरीदारी के लिए निकलेंगे। अब इस पर ही देश-दुनिया की उम्मीदें टिकी हैं। विश्व बैंक ने पूरे दक्षिण एशिया की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है और उसकी इस उम्मीद का बड़ा आधार भारत में घरेलू मांग का बढ़ना है।

मगर एक दूसरी चुनौती भी सामने खड़ी है। ऑनलाइन खरीदारी की वजह से दुकानों का, खासकर फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों में छोटे दुकानदारों का धंधा काफी परेशानी में पड़ चुका है। मॉल्स में बने बड़े-बड़े स्टोर तो बड़ी सेल लगाकर ग्राहकों को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटे वाले मुश्किल में हैं। उधर ग्राहकों के लिए यह बड़ी मुश्किल है कि वे असली और नकली सेल में फर्क कैसे करें। हर साल दो साल कोई उद्यमी रिपोर्टर किसी बड़ी चेन में जाकर बाकायदा फोटो खींचकर सबूत के साथ खबर देता है कि कैसे ये लोग दाम बढ़ाकर फर्जी सेल लगाकर दिखा रहे हैं। कई बार तो आप खुद ही दाम के ऊपर लगा स्टिकर उखाड़कर देख सकते हैं कि असली दाम क्या था।

इसके अलावा त्योहारी सीजन में खरीदारी का एक और बड़ा ठिकाना सर्राफा बाजार या ज्यूलरी स्टोर्स होते हैं। शौक भी, शगुन भी और साथ-साथ निवेश भी। सोने-चांदी और जवाहरात का बाजार भी इस मौसम में चमक जाता है। वजह यह भी है कि इसी वक्त शादी ब्याह का मौसम भी आ जाता है। इस वक्त सोने का दाम आसमान छू रहा है, यह चिंता की बात हो सकती है। लेकिन इसी में तमाम लोग यह भी देख रहे हैं कि पिछले दो-तीन सालों में जिन लोगों ने सोने में पैसा लगाया, उन्हें बाकी तमाम निवेश के मुकाबले बेहतर मुनाफा हुआ है। फिर इस कारोबार का बड़ा हिस्सा पुराने गहनों के बदले नए गहने खरीदने से भी चलता है, जिस पर दाम का कोई खास असर पड़ता नहीं है। यानी तस्वीर में कुछ चिंता की रेखाएं जरूर हैं, लेकिन उम्मीद भी है कि त्योहार खुशहाली लेकर आएंगे न सिर्फ हमारे आपके परिवार में, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

संपादकीय

बच्चों में चिड़चिड़ापन और आक्रामक व्यवहार बिगड़ रही मानसिक और भावनात्मक सेहत

आजकल बच्चों में चिड़चिड़ापन और आक्रामक व्यवहार तेजी से बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं, जो उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। यह समस्या समाज में भी व्यापक रूप से देखी जा रही है और इसे समय रहते समझकर हल करना बहुत जरूरी है। बच्चों का चिड़चिड़ापन एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन सही देखभाल, संतुलित जीवनशैली और पेरेंट्स का सकारात्मक सहयोग इसे नियंत्रित कर सकता है। बच्चों को एक स्वस्थ और खुशहाल वातावरण प्रदान करना उनकी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए जरूरी है।

चिड़चिड़ेपन के प्रमुख कारण

» डिजिटल स्क्रीन का अधिक उपयोग बच्चों का लंबे समय तक टीवी, मोबाइल और वीडियो गेम्स का उपयोग करना उनके मस्तिष्क को थका देता है। यह उनकी सोने की दिनचर्या, शारीरिक गतिविधियों और मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है।

» शारीरिक गतिविधियों की कमी पहले की तुलना आजकल बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। बाहर खेलने और दौड़ने भागने के बजाय वे ज्यादातर समय घर में ही रहते हैं, जिससे ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता और वे चिड़चिड़े हो जाते हैं।

>> असंतुलित खान-पान : जंक फूड और अस्वस्थ आहार बच्चों के मस्तिष्क और शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके कारण बच्चों में पोषण की कमी और ऊर्जा का असंतुलन होता है, जो चिड़चिड़ेपन का एक कारण बनता है। » नींद की कमी सही समय पर और पर्याप्त नींद न मिलने से बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है। नींद की कमी से बच्चे थके हुए और चिड़चिड़े रहते हैं, जिससे उनका व्यवहार भी बदलता है। >> भावनात्मक तनाव : स्कूल, घर और सामाजिक जीवन से जुड़े दबाव बच्चों में तनाव पैदा कर सकते हैं। पेरेंट्स की अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा और परीक्षा का दबाव उन्हें मानसिक रूप से थका सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन हो सकता है।

बचाव के उपाय

>> डिजिटल समय सीमित करें : बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को सीमित करें और उनके लिए शारीरिक खेलों को प्राथमिक से करें और उनकी गतिविधियों में उन्हें शामिल करें।

>> स्वस्थ आहार दें : बच्चों को संतुलित आहार, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल हों, दें। जंक फूड और शक्कर का सेवन सीमित करें, ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही से हो सके।

» नींद का ध्यान रखें : बच्चों को सही समय पर सोने की आदत डालें। 7-8 घंटे की नींद उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

>> शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएं : बच्चों को खेल और बाहरी गतिविधियों में शामिल करें। इससे उनकी ऊर्जा का सही उपयोग होगा और वे शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे। >> भावनात्मक समर्थन दें : बच्चों के साथ समय बिताएं और उनके तनाव और चिंताओं को समझने की कोशिश करें। उन्हें स्नेह और समर्थन दें ताकि वे मानसिक रूप से संतुलित रहें।

विजय गर्ग

एमबीए की डिग्री के बाद आगे बढ़ने के लिए करियर पथ

विजय गर्ग

एमबीए प्रबंधन करियर के लिए एक महत्वपूर्ण डिग्री है, जो विश्व स्तर पर नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाता है। स्नातक प्रतिस्पर्धी शुरुआती वेतन के साथ प्रबंधन सलाहकार, निवेश बैंकर, मानव संसाधन प्रबंधक, संचालन प्रबंधक, विपणन प्रबंधक और उत्पाद प्रबंधक जैसी भूमिकाएं निभा सकते हैं। कार्यक्रम विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में विश्लेषण, रणनीति और नेतृत्व में कौशल को बढ़ावा देता है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एमबीए एक ऐसी डिग्री है जिसे हमेशा प्रबंधन में एक सफल करियर के लिए संस्कार माना गया है। यह एक व्यक्ति को विभिन्न व्यावसायिक कार्यों की गहरी समझ से लैस करता है ताकि व्यक्ति विशेषज्ञता के कई क्षेत्रों में कैरियर के अवसरों का पता लगाने के लिए पर्याप्त बहुमुखी हो। एमबीए न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यधिक महत्व रखता है, जिससे व्यक्तियों के लिए विदेश में एक समृद्ध कैरियर स्थापित करना आसान हो जाता है। इसके अलावा, एक प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल से ऐसी डिग्री प्राप्त करना यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान का प्लेसमेंट सेल आपको आकर्षक वेतन पैकेज के साथ एक अच्छी तरह से स्थापित फर्म में नौकरी दिला सकता है। 1) प्रबंधन सलाहकार: यह सबसे जैविक भूमिका है जिसे बहुत से एमबीए स्नातक निभाते हैं। यह प्रोफ़ाइल आपसे व्यवसाय के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली समस्याओं की पहचान करने, स्थिति पर नज़र रखने के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ बातचीत करके मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा इकट्ठा करने, प्रचलित मुद्दों के समाधान के लिए विशेष रूप से तैयार की गई रणनीतियों को तैयार करने और कंपनी को बढ़ावा देने के लिए नई प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को शुरू करने की अपेक्षा करती है। लाभप्रदता और निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना। किसी को विश्लेषणात्मक सोच, संचार, अनुकूलनशीलता, संचार, परियोजना प्रबंधन और समस्या-समाधान जैसे कौशल को निखारना चाहिए, क्योंकि उनमें से प्रत्येक आपको कंपनी को अनिश्चित समय से आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। 2) निवेश बैंकर: यदि आपको संख्याएँ पसंद हैं, तो आप निस्संदेह निवेश बैंकिंग में सफल होंगे। एक निवेश बैंकर के रूप में, आप कंपनियों को पूंजी जुटाने और रणनीतिक रूप से उनके वित्त की संरचना करने में सहायता करेंगे। इसके अलावा, आप सर्वोत्तम संभव सौदा प्राप्त करने के लिए विलय और अधिग्रहण पर उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा, कंपनियां विभिन्न वित्तीय मामलों पर आपसे सलाह लेंगी और अच्छी तरह से सूचित कॉल करने के लिए हाल के रुझानों के आधार पर अंतर्दृष्टि मांगेंगी। इसलिए, खुद को कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में पेश करने के लिए मूलभूत ज्ञान के साथ-साथ, आपको बातचीत कौशल, नेटवर्किंग क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता हासिल करनी चाहिए। 3) मानव संसाधन प्रबंधक: एमबीए करने के बाद सबसे अधिक मांग वाली भूमिकाओं में से एक एचआर मैनेजर की भूमिका है। ये लोग प्रतिभा अधिग्रहण प्रक्रिया को संभालने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि केवल कंपनी की संस्कृति और नौकरी की आवश्यकताओं के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाने वाले उम्मीदवारों को ही काम पर रखा जाए। एक बार काम पर रखने के बाद, वे ऑनबोर्डिंग और कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की भी देखभाल करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए कर्मचारी आसानी से अपनी भूमिकाओं में बदलाव कर सकें। चूंकि वे कंपनी और कर्मचारियों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं, वे संघर्ष, कर्मचारी जुड़ाव, वेतन संरचना, कर्मचारी लाभ, श्रम कानूनों के

अनुपालन और भर्ती प्रथाओं में विविधता और समावेशन का भी ध्यान रखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनका काम दोनों पक्षों - कर्मचारी और नियोक्ता - को संतुष्ट रखना है। शुरुआती वेतन: 6-7 लाख रुपये प्रति वर्ष, जो कंपनी के आकार के आधार पर 15 लाख रुपये तक जा सकता है। 4) संचालन प्रबंधक: जैसा कि नाम से पता चलता है, एक संचालन प्रबंधक को उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए विभिन्न कार्यों में लगातार सुधार करना होता है। ऐसा करने के लिए, वेप्रक्रियाओं में अपव्यय या देरी से बचने के लिए संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना होगा और संसाधनों की खरीद और आवंटन की निगरानी करनी होगी। उनका मजबूत नेतृत्व और टीम प्रबंधन कौशल, विस्तार पर ध्यान और वित्तीय कौशल उन्हें गुणवत्ता नियंत्रण, बजट और लागत नियंत्रण, टीम विकास, परियोजना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और नई प्रौद्योगिकियों के एकीकरण जैसी जिम्मेदारियों के सफल निष्पादन में सहायता करते हैं। समय के साथ, संचालन प्रबंधक मुख्य परिचालन अधिकारी, संचालन निदेशक और महाप्रबंधक जैसी भूमिकाओं में प्रगति कर सकते हैं। शुरुआती सैलरी: 7-15 लाख रुपये सालाना. 5) मार्केटिंग मैनेजर: यह एक ऐसी भूमिका है जहां एक व्यक्ति कंपनी के उत्पाद और सेवाओं को बढ़ावा देने और उसके व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यापक विपणन रणनीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे लोगों को बाजार अनुसंधान में संलग्न होने, उपभोक्ता व्यवहार को समझने और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण करने का काम सौंपा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी प्रतिस्पर्धा में आगे रहे। इसके अलावा, वे विभिन्न चैनलों पर मार्केटिंग अभियानों की योजना बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करते हैं, और ब्रांड की आवाज़ का प्रबंधन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे KPI या प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करके मार्केटिंग रणनीतियों की सफलता को ट्रैक करते हैं और रणनीतियों में डेटा-संचालित सुधार की पेशकश करने के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं। शुरुआती वेतन: 8-15 लाख रुपये प्रति वर्ष। एफएमसीजी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के बड़े संगठनों में यह 20 लाख रुपये सालाना हो सकता है. 6) उत्पाद प्रबंधक: एक अन्य प्रोफ़ाइल जो एमबीए स्नातकों के बीच हमेशा उच्च मांग में रहती है वह है उत्पाद प्रबंधक की। उनकी प्राथमिक भूमिका किसी उत्पाद या उत्पादों की श्रृंखला के लिए रणनीतियों को परिभाषित करना है। इसके लिए, वे गहन बाजार अनुसंधान करते हैं, उपभोक्ता मांगों पर बारीकी से ध्यान देते हैं, क्रॉस-फंक्शनल टीमों के साथ मिलकर काम करते हैं, उत्पाद विकास की देखरेख करते हैं और बिक्री और विपणन में लगातार सहयोग करते हैं। एक बार जब कोई उत्पाद सफलतापूर्वक बाज़ार में आ जाता है, तो वे आवश्यक सुधार करने के लिए उसके प्रदर्शन पर नज़र रखते हैं। इस भूमिका में सफल होने के लिए व्यक्तियों को ग्राहक-केंद्रित मानसिकता, तकनीकी समझ और रणनीतिक सोच की आवश्यकता होती है।

ऑनलाइन पढ़ाई के साथ घर पर नीट युजी परीक्षा-2025 की तैयारी कैसे करें

विजय गर्ग

जैसे-जैसे नीट 2025 परीक्षा नजदीक आ रही है, कई इच्छुक मेडिकल छात्र अपने घरों में आराम से बैठकर कड़ी तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के उदय के साथ, उम्मीदवारों के पास अब प्रभावी स्व-अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे संसाधन और उपकरण हैं।

ऑनलाइन पढ़ाई के साथ घर पर नीट 2025 की तैयारी कैसे करें, इस पर एक व्यापक मार्गदर्शिका यहां दी गई है

1. नीट 2025 सिलेबस को समझें

तैयारी में उतरने से पहले, नीट 2025 पाठ्यक्रम से खुद को परिचित कर लें। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में शामिल विषयों को समझें, और प्रत्येक विषय की वजन आयु के आधार पर एक अध्ययन योजना बनाएं।

2. विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म चुनें

विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म चुनें जो एनईईटी-केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। एनईईटी उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई प्रासंगिक अध्ययन सामग्री, वीडियो व्याख्यान और अभ्यास परीक्षण मददगार होंगे।

3. एक यथार्थवादी अध्ययन कार्यक्रम बनाएं

एक अध्ययन कार्यक्रम विकसित करें जो आपकी दैनिक दिनचर्या के अनुरूप हो। अपने अध्ययन सत्रों को संकेंद्रित अंतरालों में विभाजित करें, बीच-बीच में संक्षिप्त अंतराल के साथ।

4. ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लाभ उठाएं

नियमित रूप से ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लाभ उठाएं। ऑनलाइन कई प्लेटफ़ॉर्म हैं जो एनईईटी मॉक टेस्ट प्रदान करते हैं जो परीक्षा स्थितियों का अनुकरण करते हैं। यह न केवल आपकी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करता है बल्कि समय प्रबंधन कौशल को भी बढ़ाता है।

5. वीडियो के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षण

कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अनुभवी शिक्षकों द्वारा दिए गए वीडियो व्याख्यान पेश करते हैं। वीडियो पाठ जटिल विषयों को अधिक सुलभ बना सकते हैं और प्रमुख अवधारणाओं की आपकी समझ को बढ़ा सकते हैं।

6. त्वरित रिवीजन के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग करें

ऐसे शैक्षिक ऐप्स डाउनलोड करें जो त्वरित पुनरीक्षण सामग्री प्रदान करते हैं। ऐप्स पर उपलब्ध फ़्लैशकार्ड, क्विज़ और इंटरैक्टिव अध्ययन सहायता चलते-फिरते सीखने और अंतिम समय में दोहराने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

7. ऑनलाइन संसाधनों से अपडेट रहें

नीट से जुड़ी ताजा खबरों और बदलावों से खुद को अपडेट रखें। प्रतिष्ठित शैक्षिक वेबसाइटों का अनुसरण करें, न्यूज़लेटर्स की सदस्यता लें और परीक्षा पैटर्न या पाठ्यक्रम में किसी भी संशोधन के बारे में सूचित रहें।

8. आत्म-मूल्यांकन को प्राथमिकता दें

स्व-परीक्षणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से नियमित रूप से विषयों की अपनी समझ का आकलन करें। कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें और उन विषयों पर अधिक समय आवंटित करें। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अक्सर आपके प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं।

9. स्वस्थ अध्ययन वातावरण

घर पर एक समर्पित और आरामदायक अध्ययन वातावरण बनाएं। विकर्षणों को कम करें और अच्छी रोशनी सुनिश्चित करें। एक व्यवस्थित अध्ययन स्थान आपके फोकस और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

10. ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करें

विषय विशेषज्ञों द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में भाग लें। कई शैक्षणिक प्लेटफ़ॉर्म लाइव सत्र आयोजित करते हैं जहां आप शिक्षकों के साथ बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और चुनौतीपूर्ण विषयों पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

11. संतुलित जीवनशैली बनाए रखें

हालाँकि गहन तैयारी महत्वपूर्ण है, संतुलित जीवनशैली बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद लें, नियमित शारीरिक गतिविधि में संलग्न रहें और थकावट से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में ब्रेक शामिल करें। इष्टतम शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर आवश्यक है।

निष्कर्षतः, ऑनलाइन पढ़ाई के साथ घर पर नीट 2025 की तैयारी के लिए एक अनुशासित और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रतिष्ठित ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठाकर, अपने अध्ययन कार्यक्रम के अनुरूप रहकर और एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखकर, आप आगामी नीट परीक्षा में सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

खुल गया देश का सबसे बड़ा आईपीओ, क्या आपको लगाने चाहिए पैसे?

परिवहन विशेष न्यूज

हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। इसका मतलब कि अब आप 17 अक्टूबर तक देश के इस सबसे बड़े आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। हुंडई के आईपीओ का प्राइस बैंड 1865 रुपये से 1960 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है। इसका लॉट साइज सात शेयरों का है। आइए हुंडई आईपीओ के GMP समेत पूरी डिटेल जानते हैं।

नई दिल्ली। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। यह सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का रिकॉर्ड तोड़कर अब देश का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया है। दक्षिण कोरिया की ऑटो मोटर हुंडई की भारतीय यूनिट आईपीओ से 27,870.16 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसे आज यानी 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस आईपीओ की पूरी डिटेल।

Hyundai Motor India IPO का प्राइस बैंड

हुंडई के आईपीओ का प्राइस बैंड 1,865 रुपये से 1,960 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगी। इसका लॉट साइज सात शेयरों का है। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम 13,720 रुपये निवेश करना होगा। हुंडई के शेयरों की बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग की संभावित तारीख मंगलवार, 22 अक्टूबर 2024 है।

Hyundai Motor India IPO GMP

हुंडई का आईपीओ 2003 के बाद किसी भी कार निर्माता का पहला आईपीओ है। लेकिन, इसे लेकर काफी कम उत्साह है। इसकी वजह है हुंडई का लगातार घटता ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP)। हुंडई के आईपीओ का जीएमपी शुरुआत में करीब 1200 रुपये था, जो 50 रुपये के आसपास आ गया है। अगर सितंबर के आखिरी सप्ताह से तुलना करें, तो हुंडई का आईपीओ 90 फीसदी से अधिक क्रैश हो गया है।

हुंडई के आईपीओ पर एक्सपर्ट की राय

हुंडई के आईपीओ का GMP भले ही कम हो, लेकिन अधिकतर ब्रोकरेज इसे लॉन्ग टर्म प्लान के साथ सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि हुंडई का मार्केट शेयर अच्छा है और इसके ग्रोथ करने की संभावना भी काफी अधिक है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हुंडई पर दांव लगा सकते हैं। उनका कहना है कि ऑटो सेक्टर के रिवाइव होने पर हुंडई को काफी अच्छा फायदा मिलेगा।

Hyundai ने एंकर निवेशकों से जुटाए 8,315 करोड़

हुंडई मोटर इंडिया (HMIL) ने सोमवार को एंकर निवेशकों से 8,315 करोड़ रुपये जुटाए। उसने 1,960 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 4.24 करोड़ शेयर 225 फंड्स को आवंटित किए, जो इसके प्राइस बैंड का उच्चतम स्तर था। आवंटन हासिल करने वाले एंकर निवेशकों में सिंगापुर सरकार का सॉवरेन वेल्थ फंड (GIC), न्यू वर्ल्ड फंड और फिडेलिटी शामिल थे। आवंटन में 21 घरेलू म्यूचुअल फंड्स (MF) भी शामिल थे। इनमें ICICI प्रूडेंशियल MF, SBI MF और HDFC MF शामिल हैं, जिन्होंने 83 योजनाओं के माध्यम से आवेदन किया था।

चाइनीज शेयर मार्केट के गुब्बारे की क्यों निकली हवा, क्या भारत को होगा फायदा?

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले कुछ समय से चीन के शेयर मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी। शंघाई कम्पोजिट एक ही महीने में 20 फीसदी से अधिक बढ़ गया। दुनियाभर के निवेशक और म्यूचुअल फंड हाउस चीन के शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए उतावले हो गए। लेकिन अब खेल पलट गया। चीन के शेयर मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से विदेशी निवेशक, चीन के शेयर मार्केट का ढोल पीटते नजर आ रहे थे। लेकिन, अब वो ढोल फटता नजर आ रहा है। बीते 5 दिन में चीन का प्रमुख सूचकांक-शंघाई कम्पोजिट 7 फीसदी तक गिर गया है। अब भारत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी कम हो गई है। अब भारतीय बाजार काफी हद तक स्थिर दिख रहा है। आइए जानते हैं कि चीन के शेयर मार्केट में गिरावट की क्या वजह है और भारत को इससे कैसे फायदा होगा।

चीन के शेयर मार्केट में तेजी क्यों आई थी?

चीन काफी समय से आर्थिक संकट में घिरा हुआ है। खासकर, उसका रियल एस्टेट सेक्टर। इसके चलते चीन के शेयर मार्केट का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। पिछले एक साल में शंघाई कम्पोजिट ने सिर्फ 4 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, भारत का निफ्टी50 इसी समान अवधि में करीब 27 फीसदी का जोरदार रिटर्न दे चुका है।

इससे भारतीय शेयर मार्केट का वैल्यूएशन भी काफी अधिक हो गया। वहीं, चीन वैल्यूएशन के लिहाज से काफी आकर्षक हो गया। साथ ही, चीन की शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज (China Stimulus) का एलान भी किया। इससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में बिकवाली करके चीन का रुख करने लगे।

इससे चीन के शेयर मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिली। शंघाई कम्पोजिट एक ही महीने में करीब 20 फीसदी बढ़ गया। दुनियाभर के निवेशक और म्यूचुअल फंड हाउस चीन के शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए उतावले हो गए। यह उतावलापन आम निवेशकों में भी दिखा। वे भी ऐसे फंड खोजने लगे, जो चीन के शेयर मार्केट में निवेश करता हो।

चाइनीज शेयर मार्केट धड़ाम क्यों हुआ?

दरअसल, चीन का राहत पैकेज निवेशकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। निवेशकों को लग रहा था कि चीन के वित्त मंत्री 283 अरब डॉलर के नए वित्तीय प्रोत्साहन का एलान कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने पिछले शनिवार को राहत पैकेज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन, उन्होंने किसी तरह की रकम या आंकड़ों का जिक्र नहीं किया।

एक्सपर्ट का मानना है कि अगर चीन के वित्त मंत्री 283 अरब डॉलर या इससे अधिक पैकेज का एलान कर देते, तो इसका चाइनीज स्टॉक मार्केट पर काफी सकारात्मक असर पड़ता। लेकिन, किसी रकम का जिक्र नहीं करने से निवेशकों को मायूसी हुई।

इससे उनकी इस उम्मीद को भी चोट पहुंची कि चीन की अर्थव्यवस्था हाल-फिलहाल रिवाइव हो जाएगी।

साथ ही, चीन के आयात और निर्यात के आंकड़े भी काफी निराशाजनक रहे। चीन जिन प्रोडक्ट्स की बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करता है, उस पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ भारत ने भी ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका बुरा असर उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ने की आशंका है। यह उसकी सुस्त होती अर्थव्यवस्था के लिए और अधिक चिंता की बात है।

भारत या चीन, कौन है निवेशकों की पसंद

दुनियाभर के ज्यादातर निवेशक एकमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य अधिक उज्जवल है, क्योंकि यहां ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। इसका फायदा जाहिर तौर पर शेयर मार्केट को भी मिलेगा। वहीं, चीन के लिए चुनौतियां कई मोर्चों पर बढ़ रही हैं। उसकी आबादी में बुजुर्गों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सुस्त हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर का संकट भी चरम पर है।

अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं, तो चीन की मुश्किलों में और भी इजाफा होगा। उन्होंने अपने चुनावी अभियान में चाइनीज सामानों पर 60 फीसदी तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कही हैं। अगर चीन को इस चौतरफा मार से बचना है, तो उसे बड़े आर्थिक पैकेज का एलान करना होगा। लेकिन, अभी इसके आसार नहीं दिख रहे हैं।

वहीं, भारतीय स्टॉक मार्केट की लंबी अवधि की ग्रोथ संभावनाओं बरकरार हैं। MSCI के Emerging Market Index में भारत का वेट धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इस इंडेक्स में भारत दूसरे नंबर पर है। MSCI के इस इंडेक्स के आधार पर ही तमाम ग्लोबल पैसिव फंड्स भारत में पैसा लगाते हैं। वहीं, हालिया गिरावट के बाद भारत का वैल्यूएशन भी कुछ सुधरा है। हालांकि, ज्यादा महंगे स्टॉक में गिरावट की आशंका है, लेकिन अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों में तेजी देखने को मिलती रहेगी।

ग्राम प्रधानों के लिए बड़ा अवसर, ऐसे करें भागीदारी

परिवहन विशेष न्यूज

अल्ट्राटेक-यशस्वी प्रधान में 50 हजार से अधिक प्रधानों को भागीदारी का अवसर मिलने जा रहा है। इसमें आवेदन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। सभी प्रधान निशुल्क आवेदन करेंगे। आवेदन के लिए प्रधानों को अपने मोबाइल फोन से 9687896878 नंबर पर मिस्ड काल करनी होगी। आयोजकों के अनुसार मांगी गई सारी जानकारी दे कर आवेदन पूरा किया जा सकता है।

लखनऊ: प्रदेश के प्रधानों ने अपनी नई सोच और विकास कार्यों के आधार पर विशिष्ट छवि बनाई है और 'अल्ट्राटेक-यशस्वी प्रधान' के मंच पर सम्मानित होने के लिए एक बड़ा अवसर फिर उनके सामने है। 50 हजार से अधिक प्रधानों को इसमें भागीदारी का अवसर मिलने जा रहा है।

इसमें गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों की प्रतिस्पर्धा होगी। इसके लिए प्रदेश को 13 क्षेत्र में बांटा गया है और हर क्षेत्र में ज्यूरी 20 सर्वोत्कृष्ट प्रधानों का चयन करेगी। आइए जानते हैं कि इसमें भागीदारी कैसे की जा सकती है और इसके नियम क्या हैं?

'अल्ट्राटेक-यशस्वी प्रधान' में आवेदन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। सभी प्रधान निशुल्क आवेदन करेंगे। एक प्रधान एक ही पंचायत से एक से अधिक परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सभी परियोजनाओं के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

अर्थात यदि किसी ग्राम पंचायत में तीन निर्माण कार्य हुए हैं और प्रधान तीनों को उत्कृष्ट मानते हैं तो इसके लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन के लिए प्रधानों को अपने मोबाइल फोन से 9687896878 नंबर पर मिस्ड काल करनी होगी। इससे अल्ट्राटेक यशस्वी प्रधान की वेबसाइट का लिंक प्राप्त होगा। इसी लिंक पर आवेदन पत्र मिलेगा।

आयोजकों के अनुसार मांगी गई सारी जानकारी दे कर आवेदन पूरा किया जा सकता है। उन्हीं परियोजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है, जो एक अप्रैल 2022 से 30 सितंबर, 2024 के बीच में पूर्ण हुई हों। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर, 2024 है।

इन मानदंडों पर निर्णायक मंडल लेगा निर्णय

योजना के पूर्ण होने में लगा समय
योजना को पूर्ण करने में लगी धनराशि
योजना के संवर्धन के लिए किया गया नवाचार या विशिष्ट कार्य
समाज के लिए योजना की सार्थकता
लाभार्थियों की संख्या
यह परियोजना पंचायत के लिए क्यों जरूरी थी
परियोजना की चुनौतियां एवं समाधान

बुधवार को बंद रहेंगे बैंक, जानिए किस वजह से रहेगी छुट्टी

भारत के बारे में मशहूर है कि यह त्योहारों का देश है। शायद ही ऐसा कोई महीना रहता होगा जब भारत के किसी हिस्से में कोई बड़ा त्योहार न मनाया जाता है। अक्टूबर तो वैसे भी फेस्टिव सीजन के तौर पर जाना जाता है। इसी महीने से अमूमन फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं कि किन खास मौकों पर बैंकों में छुट्टी रहेगी।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (RBI) की लिस्ट के हिसाब से बुधवार यानी 16 अक्टूबर, 2024 को बैंक बंद रहने वाले हैं। इनमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक शामिल हैं। इसकी वजह है, 16 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का त्योहार। इस दिन कोलकाता और त्रिपुरा में सभी बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, देश के बाकी हिस्सों के बैंकों में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा।

कोलकाता में होगा बुधवार को लक्ष्मी पूजन

पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजन का त्योहार काफी अहमियत रखता है। इसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार दुर्गा पूजा के कुछ दिनों बाद आता है। इसे धन समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन लोग अपने घर और दुकान सजाते हैं।

खासकर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे सुख-समृद्धि मांगते हैं। इस मौके पर कोलकाता में लक्ष्मी पूजा का भव्य आयोजन होता है। अगरतला में भी त्योहार काफी भव्यता के साथ मनाया जाता है। यही वजह है कि कोलकाता में 16 अक्टूबर 2024 को बैंकों में अवकाश रहेगा।

अक्टूबर 2024 में प्रमुख बैंकिंग अवकाश

16 अक्टूबर: लक्ष्मी पूजन (बुधवार) कोलकाता, अगरतला

17 अक्टूबर, 2024 (गुरुवार): महर्षि वाल्मीकि जयंती/कटि बिहू - कर्नाटक, असम और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मनाई जाती है।

26 अक्टूबर, 2024 (शनिवार): परिग्रहण दिवस - जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है।

31 अक्टूबर, 2024 (गुरुवार): दिवाली (दीपावली) - देश भर में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार।

साथ ही सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक दूसरे और चौथे शनिवार (12 और 26 अक्टूबर) के साथ-साथ महीने के हर रविवार को बंद रहेंगे।

राज्यों के हिसाब से बैंकों में छुट्टी

अक्टूबर त्योहारों के हिसाब से काफी अहम होता है। इस महीने अलग-अलग राज्यों में कुछ खास त्योहार मनाए जाएंगे, जिनके चलते बैंकों में अवकाश रहेगा। मिसाल के लिए, असम 17 अक्टूबर को कटि बिहू मनाएगा, जबकि जम्मू और कश्मीर 26 अक्टूबर को परिग्रहण दिवस मनाएगा। कई राज्य अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में अलग-अलग तिथियों पर दुर्गा पूजा और दशहरा मना चुके हैं।

छुट्टी के दिन कैसे होता है लेनदेन

बैंकिंग रेगुलेटर RBI छुट्टियों के शेड्यूल की देखरेख करता है। आरबीआई के लिस्ट वाली छुट्टियों के दिन आप बैंक किसी फिजिकल ब्रांच में जाकर पैसे निकालने या जमा करने से जैस काम नहीं कर सकते। यह चीज सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों पर लागू होते हैं।

हालांकि, ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। इनकी मदद से आप बिना किसी परेशानी के

पेट्रोल-डीजल के रेट हो गए अपडेट, चेक कीजिए लेटेस्ट फ्यूल प्राइस

देश की सराकरी तेल कंपनियों ने रोजाना की तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिवाइज कर दी हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मंगलवार 15 अक्टूबर को फ्यूल की कीमतें देशभर में स्थिर बनी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अलग-अलग शहरों में ग्राहक अपनी गाड़ी में पेट्रोल-डीजल पुरानी कीमत पर ही भरवा सकेंगे।

नई दिल्ली। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हर रोज सुबह 6 पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट करती हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने मंगलवार, 15 अक्टूहर के लिए भी पेट्रोल और डीजल के रेट रिवाइज कर दिए हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, आज भी फ्यूल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब कि आज भी आप पेट्रोल और डीजल पुरानी कीमतों पर ही खरीद सकते हैं।

पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट रेट कैसे करें चेक

आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट्स एसएमएस के जरिए जान सकते हैं। फोन पर RSP स्पेस पेट्रोल पंप का डीलर कोड टाइप कर 92249 92249 पर मैसेज भेजना होता है। अगर आपको अपने शहर के पेट्रोल पंप के डीलर का कोड जाना है, तो उसे आप इंडियन ऑयल की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं।

पेट्रोल-डीजल पर नहीं लगता जीएसटी

पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। इनकी रिटेल सेलिंग प्राइस एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमिशन, वैट जुड़ने के बाद फाइनल होता है। अगर आप भी गाड़ी लेकर लंबे सफर पर निकल रहे हैं, तो टंकी फुल कराने से पहले पेट्रोल-डीजल का लेटेस्ट प्राइस जरूर चेक कर लें। हम आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अलग-अलग महानगरों और शहरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत बता रहे हैं।

केंद्र सरकार की इस स्कीम ने किया कमाल, देश में बिछ रहा कारखानों का जाल

परिवहन विशेष न्यूज

कुछ साल पहले तक भारत कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। चार साल पहले तक देश में एसी में इस्तेमाल होने वाला कंप्रेशर नहीं बनता था। कई अन्य प्रमुख पा ट्र्स इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन अब स्थिति काफी हद तक बदल गई है। अब कई पाट्र्स की घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है और इसकी वजह है पीएलआई स्कीम।

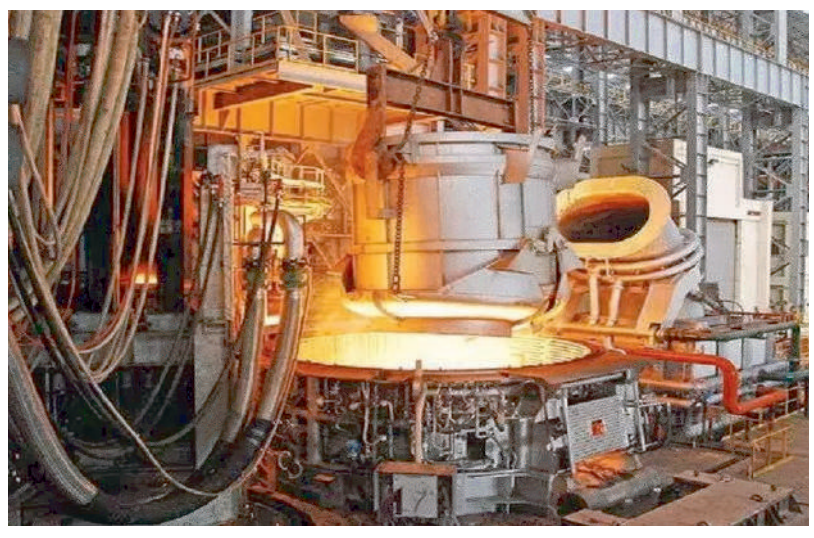

नई दिल्ली। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम की मदद से अब एसी और एलईडी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार पकड़ने लगी है। चार साल पहले तक देश में एसी में इस्तेमाल होने वाला कंप्रेशर नहीं बनाया जाता था। एसी व एलईडी के अन्य प्रमुख पाट्र्स का भी पूरी तरह से आयात किया जाता था।

अब इन पाट्र्स में घरेलू स्तर पर 20 प्रतिशत से अधिक का वैल्यू एडिशन होने लगा है जो अगले कुछ सालों में 75 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2021 में एसी और एलईडी कपोनेंट्स के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम लाई गई थी। इस स्कीम के तहत अब तक तीन चरण में आवेदन मंगाए गए।

पीएलआई स्कीम का दिख रहा है असर

पहले चरण में 15, दूसरे चरण में 40 तो तीसरे चरण में 38 कंपनियों को स्कीम के तहत उत्पादन के लिए चयनित किया गया। सोमवार को तीसरे चरण के तहत चयनित कंपनियों की घोषणा की गई। पहले चरण में चयनित 15 में से 11 कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। दूसरे चरण की 40 कंपनियों में कुछ उत्पादन शुरू कर चुकी है तो बाकी भी जल्द ही उत्पादन शुरू करने वाली है।

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव संजीव के मुताबिक, अब देश में सालाना लगभग 80 लाख कंप्रेशर का निर्माण किया जाने लगा है। पहले एसी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी कंप्रेशर का आयात किया जाता था। देश में सालाना 1.1 करोड़ एसी का निर्माण हो रहा है और इसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स का अब घरेलू स्तर पर बनने लगे हैं।

5 साल में 40 फीसदी बढ़ेगी एसी की बिक्री

एसी की बिक्री में अगले पांच साल तक 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। दो साल पहले तक यह बढ़ोतरी दर 15 प्रतिशत थी। एसी और एलईडी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, राजस्थान के निमराना व भिवाड़ी, महाराष्ट्र में पुणे और औरंगाबाद, गुजरात में सानद तो आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में स्थापित किए जा रहे हैं।

संजीव ने बताया कि तीसरे चरण के लिए जिन 38 कंपनियों का चयन किया गया है उनमें एमएसएमई स्तर की कई ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जो अब तक डायकिन, वोल्टास जैसी कंपनियों के लिए जाब वर्क करती थी। हिताची, पेनासोनिक, हेयर, डायकिन, वोल्टास, हेवल्स, ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनियां पीएलआई स्कीम के तहत एसी के कंपोनेंट्स बनाएंगी।

वहीं एलईडी लाइट्स के कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए ओरिएंट, सूर्या, क्रंपटन, कास्मो फिल्म, डिक्सन, आरके लाइटिंग जैसी कई कंपनियां आगे आई हैं। वित्त वर्ष 2028-29 तक ये 38 कंपनियां 4121 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।

राम निर्भर भारत: जहाँ श्रीराम वहीं महाबली हनुमान : अंकुर शरण

हनुमान जी का जीवन और उनके गुण भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। हमारे देश में संकट मोचन हनुमान जी का विशेष महत्व है और उनका नाम लेते ही मन में असीम शक्ति का संचार होता है। हनुमान जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का विशेष महत्व है। यह पाठ न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि आत्मबल और संकल्प शक्ति को भी बढ़ाता है। आइए समझते हैं हनुमान चालीसा का महत्व और युवाओं के लिए श्री हनुमान जी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए।

हनुमान चालीसा का महत्त्व:

हनुमान चालीसा, तुलसीदास जी द्वारा रचित 40 छंदों का एक अनुपम संग्रह है, जो हनुमान जी के अद्वितीय गुणों और उनके जीवन की महान गाथाओं का वर्णन करता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से न केवल भक्तों को संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। हनुमान जी के समक्ष बैठकर चालीसा का पाठ करने से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह हमारे मन और आत्मा को शांत करने के साथ-साथ नकारात्मक विचारों को भी दूर करता है।

युवाओं के लिए श्री हनुमान जी से प्रेरणा:

अटूट भक्ति और समर्पण: हनुमान जी की श्रीराम के प्रति भक्ति और समर्पण अपार है। आज के युवा उनसे सीख सकते हैं कि अगर मन में अटूट भक्ति और समर्पण हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हनुमान जी की तरह अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहकर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

शक्ति और धैर्य: हनुमान जी अपार शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म और मानवता के कल्याण के लिए किया। युवाओं को उनसे यह सीखना चाहिए कि शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए और जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने से ही वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन होता है।

निरंतर परिश्रम: हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि निरंतर परिश्रम और सेवा भाव के साथ कार्य करने से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कभी भी कठिनाइयों से घबराकर अपने कदम पीछे नहीं खींचे, बल्कि हर चुनौती का सामना किया और विजय प्राप्त की।

स्व-अनुशासन: हनुमान जी अपने स्व-अनुशासन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आज के समय में युवाओं को अनुशासन का महत्व समझना चाहिए और जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है।

हनुमान जी से प्राप्त होने वाली इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतार कर युवा राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 'राम निर्भर भारत' का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारे युवा हनुमान जी के गुणों को अपनाएं और श्रीराम के आदर्शों का पालन करें। हनुमान चालीसा का पाठ एक माध्यम है जो हमें हनुमान जी के गुणों को आत्मसात करने का मार्ग दिखाता है।

इसलिए, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए या मन विचलित हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री हनुमान जी से शक्ति, भक्ति, और धैर्य की प्रेरणा लें।

साइबरशाला: साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षा के मुद्दों पर फॉरेंसिक और साइबर विशेषज्ञ डॉ. वैभव से विशेष साक्षात्कार

डिजिटल युग में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इंटरनेट की सुविधा जहां एक ओर हमें अनेक सेवाओं से जोड़ती है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी इसका गलत इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दे रहे हैं। साइबरशाला ने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने और संभावित समाधान जानने के लिए फॉरेंसिक और साइबर विशेषज्ञ डॉ. वैभव से एक विशेष साक्षात्कार किया।

साइबरशाला: डॉ. वैभव, साइबर धोखाधड़ी के मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं जो आम नागरिकों को प्रभावित कर रहे हैं?

डॉ. वैभव: धन्यवाद, वर्तमान में साइबर धोखाधड़ी के कई रूप हैं जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं:

फिशिंग और स्पैम ईमेल: इसमें अपराधी नकली ईमेल या टेक्स्ट संदेश भेजकर लोगों को उनके बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं।

रैनसमवेयर हमले: रैनसमवेयर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है और फिरौती की मांग की जाती है।

ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी: फेक वेबसाइट या स्किमर डिवाइस का उपयोग कर बैंकिंग जानकारी चुराई जाती है।

सोशल मीडिया स्कैम: नकली जॉब ऑफर, लॉटरी, या फर्जी निवेश योजनाओं के माध्यम से लोगों को धोखा दिया जाता है।

साइबरशाला: क्या पहचान चोरी भी एक गंभीर समस्या है? इसे कैसे रोका जा सकता है?

डॉ. वैभव: बिल्कुल, पहचान चोरी एक बड़ी समस्या है। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को चुराकर उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसे फर्जी बैंक खाते खोलना या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। इसे रोकने के लिए लोगों को अपने व्यक्तिगत दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए, और द्विस्तरीय प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करना चाहिए।

साइबरशाला: रैनसमवेयर हमलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

डॉ. वैभव: रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं:

सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें: एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और उन्हें नियमित रूप से अपडेट करें।

डेटा बैकअप: महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप लें ताकि रैनसमवेयर हमले की स्थिति में डेटा को पुन: प्राप्त किया जा सके।

जागरूकता: कर्मचारियों और आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना आवश्यक है ताकि वे संदेहास्पद ईमेल या लिंक से बच सकें।

साइबरशाला: डार्क वेब और डीप वेब को लेकर लोगों में बहुत भय है। इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है?

डॉ. वैभव: डार्क वेब और डीप वेब का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है, लेकिन यह केवल तकनीकी ज्ञान से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकारों को कड़े कानून लागू करने चाहिए और साइबर सुरक्षा एजेंसियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना चाहिए। साथ ही, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इसके खतरों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

साइबरशाला: साइबर सुरक्षा को लेकर आम नागरिकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

डॉ. वैभव: मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि वे अपनी साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें, नियमित रूप से उन्हें बदलें, और द्विस्तरीय प्रमाणीकरण को सक्रिय करें। किसी भी संदिग्ध ईमेल, लिंक या वेबसाइट पर क्लिक करने से बचें। साइबर सुरक्षा हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है।

साइबरशाला: धन्यवाद, डॉ. वैभव, साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपके सुझावों से लोगों को साइबर अपराधों से बचने में मदद मिलेगी।

डॉ. वैभव: धन्यवाद, साइबरशाला। साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, वह सराहनीय है। आशा है कि लोग इससे लाभान्वित होंगे और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे।

भाजपा की सक्रिय सदस्यता कार्यशाला में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन माझी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

क्योंझर/भुवनेश्वर : क्योंझर के तीन दिवसीय दौरे पर आये मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी आज क्योंझर जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित सक्रिय सदस्यता कार्यशाला बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला भाजपा अध्यक्ष पार्टचूमन सबुज महंथ बर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष बिरंचि नारायण त्रिपाठी, क्योंझर सांसद अनंत नाइक, तेलकोई विधायक फकीर मोहन नाइक, पटना विधायक अखिल चंद्र नाइक, क्योंझर मेयर सुश्री निकू साहू, वरिष्ठ महासंपादक शुकदेव महान, सदस्यता जिला संयोजक एवं टोली के जिला महासचिव ज्ञानरंजन सामंत सिंहार, जिला महासचिव अनुब्रत बेहरा मंचासीन थे। आनंदपुर विधानसभा प्रत्याशी आलोका सेठी, घासीपुरा विधानसभा प्रत्याशी शंभूनाथ राउत, चंपुआ विधानसभा प्रत्याशी मुरली शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सभी जिला अध्यक्ष, महासंपादक, सदस्यता सहयोगी, जिला पदाधिकारी, प्रदेश नेता एवं मोर्चा अध्यक्ष उपस्थित थे। सदस्यता के मामले में, क्योंझर जिला भाजपा राज्य में पहले स्थान पर रही है और 2,00,000 से अधिक सदस्यों को जोड़ने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री मोहन माझी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और संगठनात्मक बैठक की। सांसद अनंत नायक ने सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाते हुए भाजपा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में क्योंझर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है।

स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्राथमिकता: के रवि कुमार

झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू

कार्तिक कुमार परिच्छा

सरायकेला, भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इसी के साथ 15 अक्टूबर 2024 की शाम साढ़े तीन बजे से झारखंड में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के. रवि कुमार ने बताया है कि चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 18 और दूसरे चरण की 22 अक्टूबर को जारी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हमारी प्राथमिकता होगी। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी हमारी प्रथमिकता सूची में है। वह मंगलवार को निर्वाचन सदन, धुर्वा में मीडिया से मुखातिब थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में तथा दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 25 अक्टूबर तक और दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। पहले चरण के नामांकनों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर और दूसरे चरण की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को होगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव को लेकर नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 01 नवंबर है। पूरी चुनावी प्रक्रिया 25 नवंबर को समाप्त हो जाएगी।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान को लेकर कोई असुविधा नहीं हो, इसे लेकर व्यापक तैयारी की गयी है। चुनाव कर्मियों को इसे लेकर प्रशिक्षित भी किया गया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का इंतजार कम हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक एप्प भी जारी करेगा, जिसके माध्यम से मतदाता मतदान केंद्रों की स्थिति, मसलन मतदान केंद्र पर कितने लोग मतदान के लिए कतार में हैं, यह जानकारी घर बैठे ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह एप्प बुजुर्ग मतदाताओं के लिए काफी लाभदायक होगा। वहीं 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को घर से मतदान की भी सुविधा रहेगी। इसके लिए उन्हें फार्म 12 डी भरना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।

पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा और संदीप सिंह भी मौजूद थे।

पार्यावरण पाठशाला: हमारे दादा-दादी से सीखें न्यूनतमवाद की कला : अंकुर

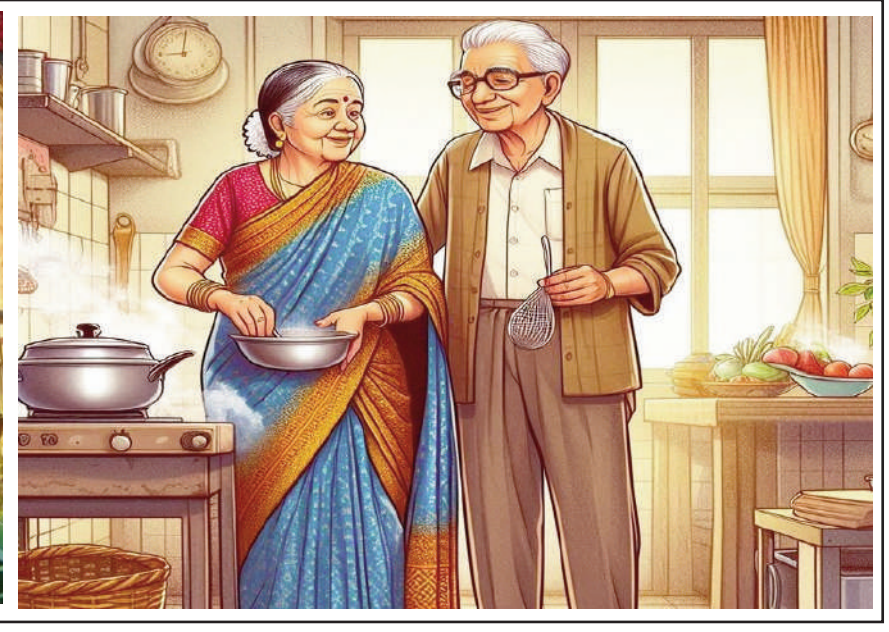

आज के आधुनिक युग में जहां हम लगातार नई-नई चीजें और उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहीं हमारे दादा-दादी का जीवन हमें एक अनमोल पाठ सिखाता है - ₹न्यूनतमवाद₹ या ₹मिनिमलिस्ट अप्रोच₹। यह एक जीवनशैली है जो हमें सिखाती है कि कैसे कम चीजों में भी खुश रहा जा सकता है और एक दीर्घायु, संतुलित, और पर्यावरण के अनुकूल जीवन जिया जा सकता है।

दादा-दादी के जीवन से न्यूनतमवाद के पाठ

हमारे दादा-दादी का जीवनकाल सादगी और स्वाभाविकता से भरा हुआ था। उनका जीवन छोटे-छोटे संसाधनों के उपयोग और आवश्यकता के अनुसार सामान के सीमित उपयोग पर आधारित था। इस जीवनशैली के कुछ मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं:

साधारण भोजन: हमारे बुजुर्ग हमेशा घर का बना सादा भोजन करते थे जो पौष्टिक और ताजगी से भरपूर होता था। बिना रसायन और प्रोसेस्ड फूड के, उनका भोजन सीधा खेत और बगीचे से आता था।

स्वनिर्मित उत्पाद: दादा-दादी घर पर ही कई चीजें खुद बनाते थे, जैसे कपड़े धोने का साबुन, मसाले पीसना, और घरेलू उपचार के लिए औषधीय जड़ी-बूटियों का प्रयोग।

आवश्यकतानुसार उपयोग: उनका मानना था कि ₹जो चीज हो, उतनी हो।₹ इसलिए वे केवल उतना ही खरीदते और उपयोग करते थे जितनी उन्हें आवश्यकता होती थी, जिससे बर्बादी की संभावना कम हो जाती थी।

पुनः उपयोग और मरम्मत: हमारे दादा-दादी किसी भी चीज को फेंकने से पहले कई बार मरम्मत करने का प्रयास करते थे, जिससे वे लंबे समय तक उसका उपयोग कर पाते थे।

न्यूनतमवाद के लाभ

स्वास्थ्य में सुधार: साधारण और प्राकृतिक भोजन का सेवन करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है।

पर्यावरण संरक्षण: कम चीजों के उपयोग और दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे का निर्माण कम होता है और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है।

मानसिक शांति: न्यूनतम जीवनशैली अपनाने से तनाव कम होता है क्योंकि व्यक्ति केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं।

वित्तीय स्थिरता: कम उपभोग करने से अनावश्यक खर्चों में कमी आती है, जिससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

न्यूनतमवाद से टिकाऊ भविष्य की ओर

यदि हम अपने जीवन में न्यूनतमवाद के सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो न केवल हम अपने दादा-दादी के जीवन के मूल्यों को सहेजेंगे, बल्कि एक टिकाऊ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने, संसाधनों के संरक्षण, और कचरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हमारे दादा-दादी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सादगी में भी सौंदर्य है और कम में भी आनंद पाया जा सकता है। उनकी जीवनशैली से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे न्यूनतमवाद को अपनाकर हम अपने जीवन को सरल, शांतिपूर्ण, और पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं।

न्यूनतमवाद की इस सीख को हम 'पार्यावरण पाठशाला' के माध्यम से आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं कि सरलता में ही स्थायित्व है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail .com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023